वार्षिक रिपोर्ट
2002-2003

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं
लोक उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2002-2003

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं
लोक उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

भारी उद्योग एवं
लोक उद्यम विभाग

मंत्रालय

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखने एवं उनके लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने के अलावा देश में पूंजीगत सामग्री एवं इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास एवं वृद्धि का सवर्धन करने के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग को मिलाकर बनाया गया है।

भारी उद्योग विभाग

भारी उद्योग विभाग भारी इंजीनियरी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का काम देखता है तथा 49 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रशासित करता है। भारी उद्योग विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। उसकी मदद के लिए 206 अधिकारियों और कर्मचारियों का एक सुगठित दल है। विभाग की सहायता के लिए एक समन्वित वित्तीय स्कंध और आर्थिक सलाहकार भी है। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी उद्यम बिजली, रेल और सड़क परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सामान और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, तेलशोधक कारखाने, पैट्रो-रसायन, जहाजरानी, वस्त्र, कागज, सीमेंट, चीनी जैसे बुनियादी उद्योगों के उपकरणों की आवश्यकता पूरी करते हैं। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजिनों, औद्योगिक गियर तथा गियर बॉक्स जैसे अनेक माध्यमिक इंजीनियरी उत्पादों के विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं।

यह विभाग विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ नियमित तालमेल रखता है और उद्योग के विकास की योजनाएं तैयार करता है। विभाग उद्योगों को नीति संबंधी प्राथमिक सहायता देता है, प्रशुल्क एवं व्यापार, टेक्नोलॅजी के क्षेत्र में सहयोग व इसमें सुधार, अनुसंधान व विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान इत्यादि करता है।

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत साज-सामान के निर्माण, परामर्श सेवा और ठेका लेने संबंधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इन सरकारी उद्यमों में 31 मार्च, 2002 तक कुल निवेश (सकल ब्लॉक) लगभग 8234 करोड़ रुपये था और लगभग 1.18 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ था (**अनुबंध-I और II**)। आटो क्षेत्र की संयुक्त कंपनी मारूति उद्योग लिमिटेड के कार्यकलापों से भी विभाग का संबंध है। इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम मशीनी यंत्रों, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/भाप/हाइड्रो टरबाइन, टर्बो जेनरेटर, रेलवे ट्रेक्शन उपकरण, प्रेशर वैसल्स, एसी रेल इंजन, प्राइम मूवर्स, विद्युत उपकरण और कृषि संबंधी ट्रैक्टर तथा स्कूटर, घड़ियां, टायर और नमक जैसी उपभोक्ता वस्तुएं बनाते हैं।

विभाग इन उद्यमों और सरकारी एजेंसियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है और इस प्रकार ग्राहकों से लम्बी अवधि तक सम्पर्क बनाए रखता है। यह विभाग विशेषकर दूरसंचार और रेलवे से संपर्क रखता है ताकि उनकी आर्डर बुक की स्थिति सुधार सके और ग्राहकों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके।

यह विभाग अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकार की समग्र सरकारी क्षेत्र नीति यथा; (i) सक्षम तौर पर व्यवहार्य सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन और पुनर्स्थापन; (ii) जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता, उन उद्यमों को बंद करना; (iii) सभी गैर-रणनीतिक सरकारी उद्यमों में सरकारी इक्विटी में कमी लाने तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए पुनर्गठन आरंभ करना तथा प्रोत्साहित करना/संयुक्त उद्यम के गठन का पता लगाना, ताकि सरकारी उद्यम प्रौद्योगिकी, विपणन और वित्तपोषण प्राप्त कर सकें, जिससे उनकी दीर्घविधिक व्यवहार्यता सुधर सके।

यह विभाग वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से सरकारी उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है, ताकि उनकी निवेश संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकें और सरकार बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्गठन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रुग्ण/घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के लिए धन जुटाता है। यह विभाग जनशक्ति के यौक्तिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी उद्यमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

नागरिक अधिकार पत्र

सरकारी क्षेत्र के उद्यम कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

विभाग प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली को व्यवस्थित करने के प्रयासों के रूप में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव और एक निदेशक क्रमशः संयुक्त सचिव (लोक-शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ii) इस विभाग के सभी मामलों को कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में पदनामित किया गया है, जो कि इस विभाग की वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी है।

(iii) पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए इस विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(iv) लोक-अदालत में विवादों के निपटान हेतु इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति का प्रतिपादन करता है। यह विभाग कार्य-निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, वित्तीय लेखांकन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करता है। लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। अपनी भूमिका निभाने के लिए वह अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों के साथ समन्वय रखता है।

इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका तथा कार्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

i) कार्यनिष्पादन में सुधार तथा मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंध, कार्मिक प्रबंध, निदेशक मंडल की संरचना, मजूरी समझौता, प्रशिक्षण, औद्योगिक संबंध, सतर्कता, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन आदि।

ii) सरकारी क्षेत्र से संबंधित सामान्य नीति।

iii) सरकारी उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश एवं अन्य दिशानिर्देश जारी करने संबंधी मामले।

iv) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नागरिकों की कतिपय श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित मामले।

v) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन से संबंधित सभी मामले।

vi) निदेशक मंडलों को शक्तियां सौंपने से संबंधित मामले।

vii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में गहन अध्ययन करना।

viii) अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले।

ix) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन का परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करना और आंकड़ों के संग्राहक के रूप में कार्य करना तथा संसद में प्रस्तुतिकरण के लिए एक वार्षिक सर्वेक्षण तैयार करना।

x) कर संबंधी मामलों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता हेतु स्थायी तंत्र।

xi) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श व पुन: प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पुनर्नियोजित करने संबंधी मामले।

इस विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं, जिनकी सहायता कुल मिलाकर 121 कार्मिकों के एक संगठन द्वारा की जाती है। संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

इस विभाग के पांच संघटक प्रभाग हैं:- वित्तीय नीति प्रभाग, समझौता ज्ञापन प्रभाग, प्रशासन एवं समन्वय प्रभाग और स्थायी मध्यस्थता तंत्र।

- वित्तीय नीति प्रभाग में लोक उद्यम सर्वेक्षण एकक, नीति आयोजना एकक, परामर्श, पुन:प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन और मजूरी नीति एकक शामिल हैं।
- प्रबंध नीति प्रभाग में कार्मिक नीति एकक, प्रशिक्षण एकक, कार्य-निष्पादन सूचक एवं कार्य प्रतिमान एकक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कक्ष शामिल हैं।
- समझौता ज्ञापन प्रभाग में समझौता ज्ञापन एकक, आंकड़ो बैंक तथा कम्प्यूटर कक्ष शामिल हैं।
- प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग में प्रशासन, पुस्तकालय, संसद और समन्वय स्कंध तथा हिन्दी कक्ष शामिल हैं।
- स्थायी मध्यस्थता तंत्र सरकारी क्षेत्र के दो अथवा उससे अधिक उद्यमों के बीच तथा सरकारी विभाग एवं सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम के बीच वाणिज्यिक विवादों को तय करने के लिए मंच प्रदान करता है।

भारी उद्योग विभाग

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ सं.
I.	भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक	11
II.	विशेषताएं	17
III.	सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यम	21
IV.	भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र	34
V.	आटोमोटिव उद्योग	40
VI.	प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास	44
VII.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	50
VIII.	सर्तकता	51
IX.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	52
X.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	53
	अनुलग्नक (I से VIII)	54
	संकेताक्षर	67

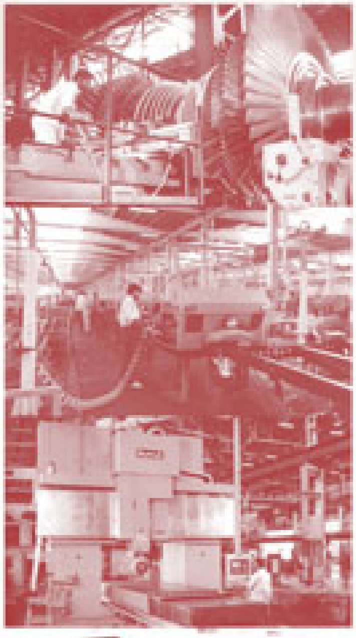

लोक उद्यम विभाग

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ सं.
I.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	71
II.	सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण	73
III.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	75
IV.	मानव संसाधन विकास	79
V.	सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	83
VI.	श्रमशक्ति योक्तिकीकरण एवं सुरक्षा तंत्र	84
VII.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	86
VIII.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	87
IX.	महिलाओं का कल्याण	88
	अनुलग्नक (I से VII)	89

भारी उद्योग विभाग

- भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक
- विशेषताएं
- सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यम
- भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र
- आटोमोटिव उद्योग
- प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास
- अल्पसंख्यकों का कल्याण
- सर्तकता
- हिन्दी का प्रगामी प्रयोग
- महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

अनुलग्नक (I से VIII)

संकेताक्षर

भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक

औद्योगिक परिदृश्य

- चालू राजकोषीय वर्ष (2002-03) की शुरूआत से भारतीय उद्योग ने आश्चर्यजनक सुधार दर्शाया है, जिसमें गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान दर्ज 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- गत वर्ष के कार्यनिष्पादन की तुलना में उद्योगों के उपयोग आधारित वर्गीकरण से भी सभी क्षेत्रों यथा आधारभूत वस्तुओं, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में भी अच्छे कार्यनिष्पादन का पता चलता है। बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुओं ने गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में दर्ज क्रमश: 2.0 प्रतिशत, -4.9 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2002-03 की अवधि के दौरान क्रमश: 4.7 प्रतिशत, 9.9 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। उपभोक्ता वस्तुओं से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं ने अप्रैल-नवम्बर, 2001-02 में दर्ज 12.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2002-03 के दौरान -6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। दूसरी ओर, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं ने अप्रैल-नवम्बर, 2001-02 में 3.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2002-03 के दौरान 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विभाग से संबंधित कुछ उद्योगों की अप्रैल-नवम्बर, 2001-02 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2002-03 की अवधि की उत्पादन और वृद्धि दरें निम्नलिखित हैं:-

	इकाई	उत्पादन अप्रैल-नवम्बर 2001-02	उत्पादन अप्रैल-नवम्बर 2002-03	वृद्धि दर (%)
औद्योगिक मशीनरी	(करोड़ रुपये)	1190.56	1234.74	3.7
मशीन टूल्स	(करोड़ रुपये)	910.76	1421.53	56.1
बायलर्स	(करोड़ रुपये)	981.10	1448.37	47.6
टरबाइन (वाष्प/जल)	(करोड़ रुपये)	355.01	336.78	-5.1
बिजली जेनरेटर	(करोड़ रुपये)	255.36	471.90	84.4
बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर	(मिलियन के.वी.ए.)	41.71	47.98	15.0
दूरसंचार केवल	(मिलियन किमी.)	213.09	140.77	-33.9
वाणिज्यिक वाहन	(संख्या)	86666	121049	39.7
यात्री कार	(संख्या)	358175	367567	2.6

- सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत प्रयास किए हैं। इन उपायों का लक्ष्य भारतीय उद्योगों के लिए बेहतर प्रचालन वातावरण उपलब्ध करा कर प्रतिस्पर्धा को सुधारना है।

भारत में चैक प्रतिनिधिमंडल के नेता और माननीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री, श्री जीरी रस्रोक के साथ माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटिल

''आटो उद्योग'' जोकि विकास का रथ है, ने गत कुछ वर्षों के दौरान उत्पादन और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भारी विकास किया है। आटो उद्योग का कुल कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जोकि 2001-02 में 82000 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुँच गया है। इस उद्योग में 4.5 लाख लोग प्रत्यक्ष और 1 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। भारतीय आटोमोबाइल क्षेत्र में विश्व स्तर के लगभग सभी भागीदार भाग ले रहे हैं।

सरकार ने आटो क्षेत्र के मात्रा और गुणवत्ता, दोनों पहलुओं की दृष्टि से और विकास तथा वृद्धि के लिए एक व्यापक नीति का अनुमोदन कर दिया है। विभाग ने आटो उद्योग के लिए परीक्षण और प्रमाणन सुविधा स्थापित करने के लिए एक दीर्घवधिक योजना भी तैयार की है, ताकि यह उद्योग पर्यावरणात्मक विनियमों और सुरक्षा मानकों का पालन कर सके। लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश से देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

इस विभाग के अधीन सरकारी उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में लगे हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यमों में से 2001-2002 में 13 ने लाभ कमाया, जबकि 36 को घाटा हुआ। 9 उद्यमों को बंद कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के 40 उद्यमों के समग्र कार्य-निष्पादन का ब्यौरा निम्न है:-

(करोड़ रुपए)

	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (अनुमानित)
उत्पादन	11670	12535
लाभ (+)/घाटा (-)	(-)908	(-)612

घाटे का कारण मांग में कमी के कारण कुछ प्रमुख उद्यमों के उत्पादन में कमी, कार्यशील पूंजी की कमी, कर्मचारियों की अधिकता, पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा निविष्टियों के मूल्यों में बढ़ोतरी है। वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने जनशक्ति के यौक्तिकीकरण के लिए 486 करोड़ रुपए और योजना निवेश के लिए 39 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है।

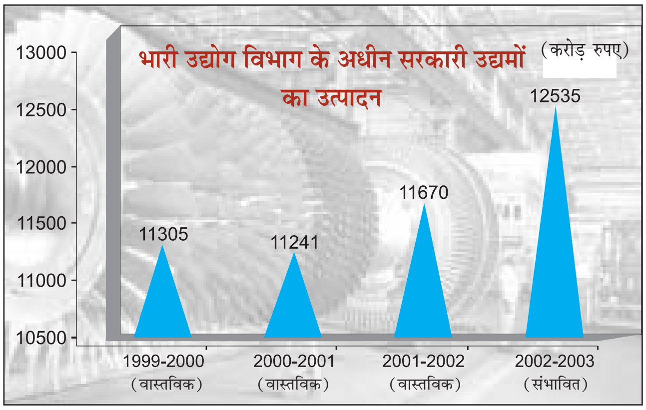

उत्पादन, लाभ/घाटा, क्रयादेश और निर्यात का विवरण अनुबंध-III, IV, VI तथा VII में दिया गया है।

वेतन मजूरी बिल और सामाजिक उपरि खर्चों का प्रतिशत अनुबंध-V में दिया गया है। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल परिसंपत्ति और संचित लाभ (+)/हानि (-) को अनुबंध-VIII में दर्शाया गया है।

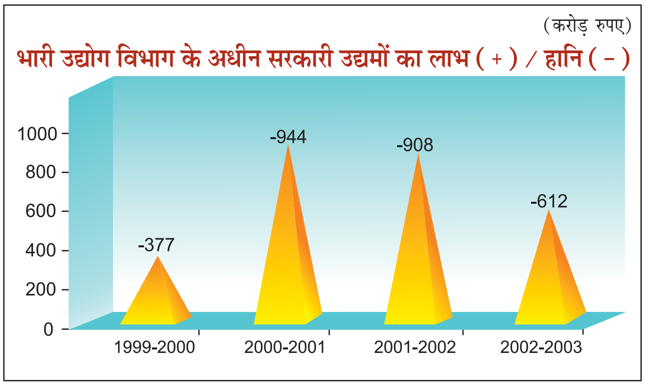

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए रणनीति

सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन की रणनीति का उद्देश्य सक्षम तौर पर व्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पुनरूद्धार करना, जिनका पुनरूद्धार नहीं हो सकता उन्हें बंद करना, सभी गैर-रणनीतिक सरकारी उद्यमों में सरकार की इक्विटी को, यदि आवश्यक हो, 26 प्रतिशत या उससे कम करना और कामगारों के हितों की रक्षा करना। इस प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन की निम्नलिखित कार्रवाइयां चल रही हैं:-

- बीआईएफआर के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरूद्धार;
- जहां उपयुक्त हो वित्तीय पुनर्गठन;
- प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण, विपणन प्रबंध आदि में लगातार पहुंच बनाए रखने के लिए संयुक्त उद्यम का गठन;
- कामगारों का यौक्तिकीकरण

बी आई एफ आर को संदर्भित सरकारी क्षेत्र के उद्यम

विभाग के सरकारी क्षेत्र के 49 में से 29 उद्यम बीआईएफआर को संदर्भित हैं। इनमें से बीआईएफआर ने 12 उद्यमों को पुनर्जीवित करने की योजना को मंजूरी दे दी है और इन पुनरूद्धार योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 654 करोड़ रुपये की राशि जुटाना तथा वित्तीय पुनर्गठन के लिए 2103 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 3 सरकारी उद्यमों के मामले में पुनरूद्धार योजना असफल हो गई है और उन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है। ये सरकारी उद्यम भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि., नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. और आरबीएल लि. हैं।

सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों का पुनर्गठन

बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार योजनाओं के अलावा, सरकार ने स्वयं निम्नलिखित 7 सरकारी उद्यमों के मामले में पुनर्गठन योजनाएं अनुमोदित की हैं। इन पुनर्गठन योजनाओं में वित्तीय, व्यावसायिक और संगठनात्मक पुनर्गठन शामिल है, जिसमें 531 करोड़ रुपए की नई राशि और 1443 करोड़ रुपए का पुनर्गठन शामिल है।

(i) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)
(ii) एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड (ए.वाई. एण्ड कं.)
(iii) नेपा लिमिटेड (नेपा)
(iv) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)
(v) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)
(vi) एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी)
(vii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि. (ईपीआई),

बीआईएफआर को सौंपे गए 29 सरकारी उद्यमों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:

(i)	ऐसे मामले, जिनमें बीआईएफआर ने पुनरूद्धार करने के लिए योजना को मंजूरी दी है (बंद किए जाने वाले 3 मामलों को छोड़कर)	**9**	
		(i)	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर लिमिटेड,
		(ii)	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड,
		(iii)	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड,
		(iv)	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड,
		(v)	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
		(vi)	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,*
		(vii)	जेसप एण्ड कम्पनी,
		(viii)	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
		(ix)	बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड,
(ii)	ऐसे मामले, जिनमें बीआईएफआर ने बंद करने की सिफारिश की है।	**11**	
		(i)	नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
		(ii)	टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
		(iii)	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड,
		(iv)	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड,
		(v)	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
		(vi)	माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन ऑफ इंडिया,
		(vii)	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड
		(viii)	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड
		(ix)	आरबीएल लिमिटेड
		(x)	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
		(xi)	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन,
(iii)	प्रक्रिया के अधीन मामले	**9**	
		(i)	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
		(ii)	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
		(iii)	नेपा लिमिटेड,
		(iv)	प्रागा टूल्स लिमिटेड,
		(v)	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
		(vi)	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
		(vii)	भारत वैगन इंजी. कं. लि.
		(viii)	हिन्दुस्तान केबल्स लि.
		(ix)	एण्ड्रयू यूले एंड कं. लि.

* स्कूटर्स इंडिया लि. से संबंधित पुनरूद्धार योजना सफल रही है और यह सरकारी उद्यम गत कुछ वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है तथा बीआईएफआर की जांच-सीमा से बाहर आ गया है।

संयुक्त उद्यम का गठन/विनिवेश

पहले से आरंभ किए जा चुके कुछ पुनर्गठन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की एक सहायक कंपनी दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि. की 1996 में मैसर्स एसोसिएट सीमेंटस कं. लि. (एसीसी) को बिक्री।
- सीसीआई के येरागुंटला संयंत्र की 1998 में इंडिया सीमेंटस लि. को बिक्री।
- एंड्रयू यूले एंड कं. (ए वाई एंड कं.) के बेल्टिंग प्रभाग का 1999 में जर्मनी की मैसर्स फिनिक्स के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में परिवर्तन, जिसमें भागीदार की इक्विटी धारिता 74% है और शेष 26% एवाई एंड कं. के पास है।
- बीबीयूएनएल की सहायक कंपनी लगन जूट मशीनरी कं. लि. (एलजेएमसी) का एक संयुक्त उद्यम के रूप में परिवर्तन और कंपनी के प्रबंधन का संयुक्त भागीदार को जुलाई, 2000 में हस्तांतरण।
- 28 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश/संयुक्त उद्यम गठित करने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिनमें से 16 मामलों में विनिवेश मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है और शेष 12 सहायक सरकारी उद्यमों के संबंध में भारी उद्योग विभाग में कार्रवाई की जा रही है।

जनशक्ति को तर्कसंगत बनाना

इस विभाग के सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है, ताकि अतिरिक्त कर्मचारियों को कोई कठिनाई पहुंचाए बिना अलग किया जा सके। वर्ष 1992-93 से वर्ष 2001-2002 तक की 10 वर्ष की अवधि में करीब 70,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है, जिस पर लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह विभाग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी के बदले में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/संस्थाओं और जनता को बांड जारी करने के लिए सरकारी उद्यमों को प्रोत्साहित करता रहा है और सरकार इस व्यय को पूरा करने के लिए ब्याज सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/अजैव्य उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पृथककरण योजना (वीएसएस) की शुरूआत

सरकार व्यवहार्य एवं विश्वसनीय पुनरूद्धार योजनाओं का समर्थन करती रही है। कुछ ऐसे सरकारी उद्यम हैं, जिन्हें बीआईएफआर/विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा अजैव्य माना गया था। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी और निम्नलिखित सरकारी उद्यमों को बंद कर दिया गया है:-

(i) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि. (बीपीएमई)

(ii) वेबर्ड इंडिया लि. (डब्ल्यू आई एल)

(iii) टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लि. (टैफको)

(iv) रिहैबीलेटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. (आरआईसी)

(v) नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनबीसीआईएल)

(vi) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि. (एमएएमसी)

(vii) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल)

उपर्युक्त सात सरकारी उद्यमों के अलावा, एचएमटी लि. की चार अव्यवहार्य इकाइयों (हैदराबाद स्थित वॉच केस डिवीजन, लैम्प डिवीजन, सेण्ट्रल मेटल फोर्मिंग संस्थान और गुवाहाटी में छोटी बैटरी इकाई) और बर्न स्टेण्डर्ड कं. लि. (बीएससीएल) की घाटे वाली रिफ्रेक्ट्री इकाइयों तथा जेलिंघम यार्ड, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल) की टांगड़ा इकाई को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर बंद कर दिया गया है।

इसके अलावा, बीआईएफआर ने भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि. और आरबीएल लि. को बंद करने की सिफारिश की है।

इन सरकारी उद्यमों के कामगारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के समान लाभ दिए जाने वाली स्वैच्छिक पृथककरण योजना (वीएसएस) आरंभ की है। वीएसएस के अंतर्गत लाभ औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन दी जाने वाली क्षतिपूर्ति से काफी अधिक हैं। लगभग 9000 कर्मचारियों के पृथक्करण के लिए 1998-99 से 2001-2002 में वीएसएस

भेल द्वारा टर्नकी आधार पर बाघाबाड़ी, बांग्लादेश में चालू किया गया 100 मेवा. का गैस टरबाइन आधारित विद्युत संयंत्र

की शुरुआत से बजटीय सहायता के रूप में सरकार ने 572 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्नों और मिनी रत्नों को स्वायत्तता

भेल नवरत्नों में से एक है। बाहर से दक्ष व्यावसायिकों को शामिल करके कम्पनी के बोर्ड को सुदृढ़ बनाया गया है। पूंजी व्यय, रणनीतिक गठबंधन करने और मानव संसाधन विकास की नीतियां बनाने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

समझौता ज्ञापन

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने तथा उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के वास्ते अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार ने समझौता ज्ञापन के विचार को स्वीकार किया है और उसे लागू किया है। वर्ष 2002-2003 में सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 8 उद्यमों ने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:-

1. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.

2. भारत भारी उद्योग निगम लि. (धारक कम्पनी)

सहायक कम्पनियां:-

(i) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.

(ii) जेसप एंड कम्पनी लि.

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.

(iv) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.

(v) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.

3. भारत यंत्र निगम लि. (धारक कंपनी)

सहायक कम्पनियां:-

(i) भारत हैवी प्लेट एंड वैसल्स लि.

(ii) भारत पम्पस एंड कंप्रैशर्स लि.

(iii) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.

(iv) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

(v) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि.

(vi) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.

4. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

5. एंड्रयू यूले एंड कंपनी लि.

6. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

7. एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी)

सहायक कम्पनियां:-

(i) एचएमटी मशीन टूल्स लि.

(ii) एचएमटी वाचेज लिमिटेड

(iii) एचएमटी चिनार वाचेज लि.

8. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

सहायक कम्पनियां:-

(i) हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि.

सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली कुछ कंपनियां, धारक कंपनी हैं, जिनकी अनेक सहायक कंपनियां हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। कुल 49 सरकारी उद्यमों में से सहायक कंपनियों सहित 21 सरकारी उद्यमों को वर्ष 2000-03 के दौरान एमओयू के अंतर्गत लाया गया है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 49 सरकारी उद्यमों में से निम्नलिखित सरकारी उद्यम/इकाइयाँ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (नौगांव और कच्छाड़ पेपर मिल्स), असम।

(ii) नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, नागालैंड।

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (बोकाजान इकाई), असम।

(iv) एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड (चाय बागान), असम।

ये सरकारी उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के उत्पादन में लगी हैं। सरकार की नीति के अनुसार इस विभाग के बजट का 10% उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई कुछ बड़ी योजनाओं में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोकाजान इकाई के लिए ओवरहैड क्रेन की स्थापना तथा विद्युत उत्पादन हेतु डी.जी सैट और असम में एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड के चाय बागान का नवीकरण शामिल है। गत तीन वर्षों, अर्थात 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किया गया पूंजीगत निवेश क्रमश: 21.50 करोड़ रुपए 4.50 करोड़ रुपए, और 7.12 करोड़ रुपए रहा है।

विशेषताएं

1. केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने पूंजीगत माल उद्योग के मुख्य कार्यपालकों की एक बैठक में भाग लिया। यह उद्योग गत दो वर्षों से उत्पादन में गिरावट का सामना कर रहा है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने उनके क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अनेक मुद्दों का उल्लेख किया और इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की।

2. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने मई 2002 में भारी उद्योग विभाग के अधीन प्रमुख सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की और मुख्य कार्यपालकों को विश्वव्यापी मानकों के बराबर अपना कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए कदम उठाने का परामर्श दिया।

3. विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों और सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान एक कार्य दल गठित करने की मांग की गई, ताकि पूंजीगत माल के लिए निर्यात बाजारों की पहचान की जा सके और इस क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं पर काबू पाया जा सके। तदनुसार, भारी उद्योग विभाग ने पूंजीगत माल उद्योग के विकास और वृद्धि से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए एक अंतर-मंत्रालययी समिति तथा पूंजीगत माल के निर्यात के संबंध में एक कार्य-दल गठित किया है।

4. सरकारी उद्यमों की जैव्यता सुधारने के लिए और राजकोष पर वेतन के भुगतान के बोझ को कम करने तथा विनिवेश/संयुक्त उद्यम गठन के लिए सरकारी उद्यमों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य इस वर्ष के दौरान जन-शक्ति योक्तिीकरण पर अतिरिक्त बल दिया गया। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के वर्ष 2000-01 में लगभग 12,500 कर्मचारियों की तुलना में 2001-02 के दौरान 21,000 से भी अधिक कर्मचारियों ने वीआरएस/वीएसएस का लाभ उठाया। सरकार ने 2000-01 में 636 करोड़ रुपये की तुलना में 2001-02 के दौरान संविधिक देयताओं सहित 762 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की है। चालू वर्ष 2002-03 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है।

5. दिनांक 26.11.2002 को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

एचएमटी, बंगलौर संयंत्र में माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटिल

6. निगम पुनर्गठन संबंधी यूएनडीपी परियोजना पूरी की गई और सचिव (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) की अध्यक्षता वाली परियोजना संचालन समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट अनुमोदित की गई।

7. भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों का सम्मेलन।

   भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों का एक सम्मेलन दिनांक 9 अक्टूबर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित किया

गया। भूमंडलीयकरण/निर्यातों के लिए उभरती हुई रणनीतियां, जनशक्ति योक्तिकीकरण, बंद सरकारी उद्यमों की परिसम्पत्तियों का निपटान, खुले बाजार के वातावरण में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के लिए प्रबंधकीय प्रयासों और समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे गहरी चिंता के प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान व्यवसाय वातावरण में घरेलू और विश्वव्यापी मैदान में भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के लिए अवसरों का पता लगाने तथा उनका कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए सहयोग और अनुभव को इकट्ठा करने के वास्ते एक समिति गठित की गई।

8. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) से संबंधित मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) भेल ने निजी नियोजन द्वारा और बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया द्वारा 200 करोड़ रुपये तक के अंशदान को प्रतिधारित रखने के विकल्प के साथ 300 करोड़ रुपये के अपरिवर्तनीय, प्रत्याभूत, पुनर्विमोच्य कर-योग्य बांडों को जारी करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इस निर्गम से 980 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसके बदले भेल ने 8.85% की कूपन दर पर 500 करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये के अधिक अंशदान सहित) की राशि बनाए रखी है।

(ii) भेल ने बंग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड, वाघाबाड़ी, बंग्लादेश के लिए टर्नकी आधार पर सबसे पहला 124 मेगावाट आईएसओ दर्जे का गैस टरबाइन आधारित विद्युत संयंत्र सफलतापूर्वक चालू करके एक भारी सफलता प्राप्त की है।

(iii) भेल ने तमिलनाडु में एक विद्युत परियोजना के लिए उच्च दक्षता वाले पारिस्थितिकी अनुकूल एडवांस क्लास गैस टरबाइन के लिए आदेश प्राप्त किया। यह 291 करोड़ रुपए की लागत वाला 101 मेगावाट संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु के कुट्टालम में तमिलनाडु बिजली बोर्ड के लिए ईपीसी आधार पर लगाया जाएगा और इसे 21 महीने के समय में पूरा किया जाएगा।

(iv) भेल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के लिए कृष्णानगर, पूर्वी दिल्ली में 33 केवी ग्रिड उपकेन्द्र चालू किया है। इस उपकेन्द्र के चालू होने से पूर्वी दिल्ली को लगभग 40 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होगी।

(v) भेल ने समय से पहले केवल 39 महीने में सिम्हाद्रि ताप विद्युत परियोजना की पहली 500 मेगावाट इकाई को मेगा ग्रीनफील्ड परियोजना के साथ-साथ टर्नकी आधार पर क्रियान्वित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सिम्हाद्रि टीपीएस (2×500 मेगावाट) की स्थापना से विद्युत की कमी वाले आंध्रप्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में काफी सुधार हो जाएगा, क्योंकि यह उत्पादित सारी विद्युत इस राज्य को आपूर्ति की जाएगी।

(vi) भेल ने तमिलनाडु में एक ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एक बड़ा आदेश प्राप्त किया है। भेल की क्षमता में विश्वास कायम रखते हुए चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (सीपीसीएल) ने चेन्नई में अपनी रिफायनरी विस्तार परियोजना के लिए 40 मेगावाट (गैस आधारित सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र के वास्ते लगभग 174 करोड़ रुपए का आदेश दिया है।

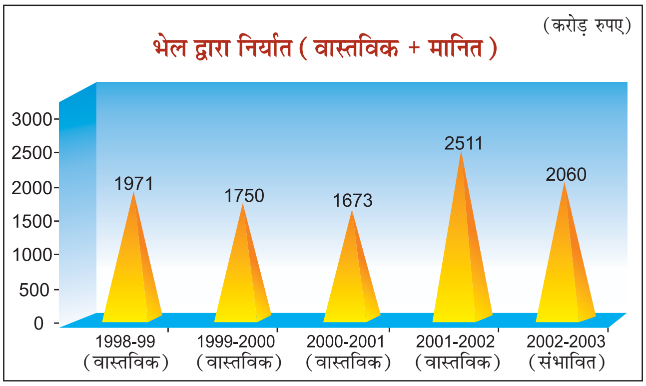

(vii) भेल के कर्मचारियों ने स्थापना से लेकर लगातार सोलहवें वर्ष प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार प्राप्त किए हैं – यह पुरस्कार उच्च उत्पादकता, उन्नत गुणवत्ता, अधिकाधिक सुरक्षा और विदेशी मुद्रा बचत के मामले में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाने वाला देश का उच्चतम सम्मान है।

(viii) ओएनजीसी द्वारा तटीय और अपतटीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तेल क्षेत्र उपस्करों की आपूर्ति, उन्नयन और साफ-सफाई के लिए भेल और ओएनजीसी ने एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) निष्पन्न किया है।

(ix) ''भारी सेवा उद्यम'' श्रेणी में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित ''राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार'' भेल को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विश्वव्यापी मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए है।

(x) भेल ने 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्र की उभरती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए वेरिएबल पिच एक्सियल फ्लो के डिजाइन और विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के वास्ते मैसर्स टर्बो लुफटैक्नीक, जीएमबीएच (टीएलटी), जर्मनी के साथ एक तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(xi) भेल ने ओमान की सल्तनत में 140 मेगावाट गैस टरबाइन आधारित टर्नकी विद्युत संयंत्र के लिए 267 करोड़ रुपए लागत का एक निर्यात आदेश प्राप्त किया।

(xii) भेल ने न्यू मंगलौर पत्तन न्यास में अपनी सबसे पहली आधुनिक पोत यातायात प्रबंध प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया।

(xiii) भेल ने प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए सेंज, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश) में स्थित पार्बती एचईपी के लिए लगभग 335 करोड़ रुपये मूल्य वाली 800 मेगावाट क्षमता की प्रथम मेगा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) की स्थापना के लिए एनएचपीसी से आदेश प्राप्त किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से श्रम भूषण पुरस्कार प्राप्त करते हुए भेल के श्री के. शिवदास

9. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) को उन्नत आईएसओ-9001:2000 प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसमें ईपीआई के सभी प्रचालनों के क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि अनेक अन्य कंपनियों के संबंध में विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं।

10. ईपीआई ने 2001-02 के दौरान 396.81 करोड़ रुपए का सर्वकालीन उच्चतम कुल कारोबार प्राप्त किया है, जोकि गत वर्ष के दौरान प्राप्त 212.52 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 86.72% की वृद्धि दर दर्शाता है। कंपनी ने 2001-02 के दौरान 595.56 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश प्राप्त किए, जोकि गत वर्ष के 311.23 करोड़ रुपए की तुलना में 91.36% अधिक हैं।

11. इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) ने निम्नलिखित आदेश प्राप्त किए :-

(i) द्वारका, नई दिल्ली में 400 एचआईजी मकानों के निर्माण और सीपीसीएल रिफाइनरी-III विस्तार परियोजना, चेन्नई के लिए सिविल और ढांचागत निर्माण कार्य तथा कोविलकल्लपल, तमिलनाडु में जीसीएस की स्थापना के लिए 71.15 करोड़ रुपए मूल्य की दो परियोजनाएं।

(ii) बंगलौर में डब्ल्यू.एस. और सीवेज सुविधाएं प्रदान करने तथा डीडीए द्वारा वसंत कुंज में मकानों का निर्माण करने के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं।

12. ईपीआई उन दस सर्वोच्च सरकारी उद्यमों में शामिल है, जिन्हें वर्ष 2000–01 के लिए एमओयू लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्कृष्टता के लिए मैरिट प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

13. ईपीआई को टंकारा – गौरीदाद बल्क वाटर पाइपलाइन परियोजना (जिला राजकोट) को समय पर पूरा करने के लिए गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया तथा यह पुरस्कार यह गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया।

14. जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) की 72% इक्विटी की बिक्री के लिए मूल्य बोलियों का विनिवेश कार्रवाई के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया।

15. सरकार ने सुजुकी मोटर कारपोरेशन जापान (एसएमसी) के साथ एक संशोधित संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए है, जिसमें एसएमसी को राइट्स निर्गम के लिए मूल्य और 1000 करोड़ रुपए की राशि के नियंत्रण प्रीमियम का भुगतान करने के बाद अपनी इक्विटी को 50% से बढ़ाकर 54.2% करने की अनुमति दी है।

16. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा अपनी जनशक्ति 2122 से घटाकर 1995 कर दी है और बोकारो स्थित अपने अजैव्य कार्यस्थल को बंद कर दिया है, ताकि समग्र व्यय कम किया जा सके। कंपनी आरक्षण के चलते बीएसएनएल से टेलीकाम एक्सचेंजों के लिए 12.21 करोड़ रुपए के आदेश सहित 16.73 करोड़ रुपए का आदेश प्राप्त करने में सफल रही है।

17. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर, जिला कोट्टायम, केरल ने बिना अधिक लागत और समय के निर्धारित समयानुसार 52.20 करोड़ रुपए लागत वाले अपने 100 टीपीडी डी–इंकिंग संयंत्र को 11 दिसंबर, 2002 को चालू कर दिया है।

18. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. की सेलम इकाई को सेरामिक उत्पादों के उत्कृष्ट निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए नवम्बर, 2002 में वर्ष 2001–2002 के लिए 'केपक्सिल' पुरस्कार प्रदान किया गया।

19. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को इसके पर्यावरणीय प्रयासों और उपलब्धियों के लिए ग्रीनटेक फाऊंडेशन, नई दिल्ली द्वारा ग्रीनटेक पर्यावरणीन उत्कृष्टता रजत पदक, 2001–2002 प्रदान किया गया।

सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यम

एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लि.

एंड्रयू यूल एंड कंपनी (ए वाई एंड कम्पनी) औद्योगिक पंखे, चाय, कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण निवारण उपकरणों जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के काम में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिये चाय की खेती, उत्पाद और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कम्पनियां 1 अप्रैल, 1986 को एंड्रयू यूल एंड कम्पनी में शामिल हो गई। ट्रांसफार्मर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करके एंड्रयू यूल एंड कम्पनी समूह में शामिल कर दी गई। कंपनी रुग्ण हो गई है और हाल ही में बीआईएफआर को सौंप दी गई है। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी और दो बड़ी सहायक कम्पनियां अर्थात दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी और टाइड वाटर आयल कम्पनी भी शामिल है। पुनर्गठन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1 फरवरी, 1999 से कम्पनी के बैल्टिंग प्रभाग को संयुक्त उद्यम कम्पनी में बदल दिया गया है और नयी कम्पनी की 74 प्रतिशत शेयर पूंजी जर्मनी की मैं. फीनिक्स ए जी के पास है और 26 प्रतिशत मै. एंड्रयू यूल एंड कम्पनी के पास है। 2002-2003 में एंड्रयू यूल एंड कं. का उत्पादन 139 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। इसकी सहायक और संबद्ध कंपनियों सहित इस कंपनी के व्यापक पुनर्गठन पर विचार किया गया है।

हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.

इसकी स्थापना मुद्रण और लेखन सामग्री संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1922 में की गयी थी। यह एंड्रयू यूल एंड कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। वर्ष 2002-2003 में कम्पनी का उत्पादन 7.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त उद्यम के गठन/विनिवेश करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं और इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.

कम्पनी की स्थापना देश की विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए उपस्करों की मांग को विशेष रूप से पूरा करने के उद्देश्य से की गयी थी। भेल विद्युत क्षेत्र में सभी उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति करने वाली एकमात्र प्रमुख कम्पनी है। इसके अलावा, संपूर्ण भारत और विश्व में परियोजना स्थल और क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा इसके 14 कारखाने, 8 सेवा केन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केन्द्र हैं। कम्पनी को सरकारी क्षेत्र की **'नवरत्न'** कम्पनियों की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2001-02 में एमओयू लक्ष्यों की तुलना में भेल के कार्यनिष्पादन के लिए इसे 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है।

कम्पनी ने कारोबार के नये क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जहां इसके मौजूदा आधारभूत ढांचे, कौशल और क्षमताओं का अधिक लाभप्रद उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे कुछ नए क्षेत्रों में वेस्ट हीट रिकवरी बायलर, गैस टरबाइन, एसी लोको, सेरालिन इंसुलेटर्स, कंगन वाली गढ़ाई और खारापन दूर करने के संयंत्र शामिल हैं।

कम्पनी ने एक जर्मनी की मै. सीमेन्स के साथ और दूसरा अमरीका की मै. जनरल इलैक्ट्रिक के साथ, दो संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की है। ये उपक्रम क्रमश: ताप बिजली घरों के रखरखाव/नवीकरण और गैस टरबाइनों के रखरखाव से संबंधित हैं।

2002-2003 में कम्पनी का कारोबार 7600 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

भेल द्वारा आंध्र प्रदेश में स्थापित सिम्हाद्रि ताप विद्युत केन्द्र

भारत भारी उद्योग निगम लि.

बाहर एजेंसियों के साथ अंतर-इकाई संपर्क और बेहतर समन्वय द्वारा तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय प्रभाव लाने के उद्देश्य से धारक कम्पनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी बी यू एन एल) का गठन 1986 में किया गया था। इसकी निम्नलिखित सहायक कम्पनियां हैं:-

1. बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड

   सहायक कम्पनियां:

   (i) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बी बी वी एल)*

   (ii) आर बी एल लिमिटेड*

2. जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड

3. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड

4. ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड

5. भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्पनी लि. (बंद कर दी गई है)

   सहायक कंपनी:

   (i) वेबर्ड (इण्डिया) लि. (डब्ल्यू आई एल) बंद कर दी गई है।

6. ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कम्पनी लि.

वर्ष 2002-2003 के दौरान सभी प्रचालनरत सहायक कंपनियों सहित धारक कम्पनी का उत्पादन 482 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

*बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लि. और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लि. का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप दिसंबर, 1976 में बर्न स्टैडर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल) को निगमित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयां हैं। बीएससीएल के विनिर्माण संबंधी मुख्य उत्पादों में वैगन्स, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइन्ट्स एंड क्रासिंग, बोगियां, राख नियंत्रण संयंत्र, कोयला संचालन संयंत्र इत्यादि शामिल हैं। कंपनी रुग्ण है और बीआईएफआर को संदर्भित है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत एक पुनरूद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है। कम्पनी की घाटा उठाने वाली 7 रिफ्रेक्ट्री इकाइयों और जेलिंघम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद बंद कर दिया गया है।

सरकार कंपनी का संयुक्त उद्यम बनाने/विनिवेश करने के लिए संभावनाओं का पता लगा रही है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 204.82 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

जेसप एंड कम्पनी लि.

जेसप एंड कंपनी लि. का सरकार ने 1973 में अधिग्रहण किया था।

कंपनी उत्पादों की विभिन्न श्रृंखलाओं जिसमें रेलवे रॉलिंग स्टॉक, अर्थमूविंग उपस्कर, विशाल रेंज के क्रेन, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, हाइड्रालिक गेट, पेपर मशीनरी, माइनिंग उपस्कर आदि शामिल हैं, के डिजाईन बनाने एवं निर्माण में लगी है। कंपनी रुग्ण है एवं बीआईएफआर को संदर्भित है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार योजना के अनुसार सरकार ने 43 करोड़ रुपए के नए निवेश और 141 करोड़ रुपए की वित्तीय पुर्नसंरचना राशि जारी कर दी है। तथापि, कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार नहीं हुआ। सरकार ने 72% इक्विटी के हस्तांतरण के लिए एक निजी कंपनी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था और इस उद्यम के पुनरुद्धार के लिए बीआईएफआर का अनुमोदन सितम्बर, 2002 में प्राप्त हो गया था। तथापि, एक रिट याचिका के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुमति प्रतीक्षित है। वर्ष 2001-2002 के दौरान कंपनी का उत्पादन 64 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ब्रेथवेट एंड कंपनी

राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप, सरकार ने दिसम्बर 1976 में कंपनी को अपने अधीन ले लिया था। कंपनी की 3 निर्माणकारी इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स, (iii) एंगस वर्क्स है, जो मुख्य रूप से रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स और सामान्य एवं विशेष कार्यों के लिए क्रेन्स, जिसमें कंटेनर हैंडलिंग क्रेन्स,

रेल-माउंटिंग डीजल लोको, ब्रेक डाउन क्रेन्स, जूट कार्डिंग मशीन्स और जूट उद्योग के लिए रॉल फीडर्स आदि शामिल हैं, के निर्माण में लगी हैं। कंपनी रुग्ण है और बीआईएफआर को संदर्भित है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत एक पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है। पुनरूद्धार योजना के अनुसार सरकार ने 26.68 करोड़ रुपए के नए निवेश और 144 करोड़ रुपये की वित्तीय पुनर्संरचना राशि जारी कर दी है। सरकार कंपनी का विनिवेश करने/संयुक्त उद्यम बनाने की संभावनाओं का पता लगा रही है, जिसके लिए सलाहकारों ने रुचि दर्शाने के प्रस्ताव (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 99.88 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ब्रेथवेट द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति की गई मालदा स्थित 150 एमटी क्षमता की एलपीजी बुल्लेट्स

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि.

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (बी डब्ल्यू ई एल) का गठन दिसम्बर, 1979 में ब्रिटेनिया, मोकामा, बिहार और आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर, बिहार के राष्ट्रीयकरण के बाद किया गया था। कंपनी के मुख्य उत्पादों में रेलवे वैगन, स्क्रू पाइल ब्रिज, इस्पात ढांचे, ग्रे आयरन कास्टिंग्ज आदि शामिल हैं। कंपनी द्वारा विविधीकरण करने और तेल टैंकों तथा परियोजना स्थलों पर संरचनात्मक गढ़ाई तथा स्थापन कार्य जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वैगन आदेशों पर निर्भरता कम हो सके। कंपनी रुग्ण हो गई है, इसलिए इसे बीआईएफआर को संदर्भित किया गया है। सरकार कंपनी का संयुक्त उद्यम बनाने/विनिवेश करने के लिए संभावनाओं का पता लगा रही है। सलाहकारों द्वारा रुचि दर्शाने के प्रस्ताव (ईओआई) आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 में कम्पनी का उत्पादन 74.80 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कं. लि.

ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (बीबीजे) का गठन ब्रेथवेट, बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड के रूप में 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए किया गया था। बीबीजे अगस्त, 1987 में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कम्पनी बन गयी।

कम्पनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी के निर्माण का कार्य करती है। कम्पनी ने रस्सों वाले लम्बे सड़क पुलों के निर्माण की आधुनिक टेक्नोलाजी हासिल कर ली है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। कंपनी को संयुक्त उद्यम में बदलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं। सलाहकारों द्वारा रुचि दर्शाने के प्रस्ताव (ईओआई) आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पक्षों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई पूरी कर ली गई है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 38 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

बीबीजे द्वारा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 12 × 90 मी. कृष्णा सेतु का निर्माण

भारत यंत्र निगम लि.

भारत यंत्र निगम लिमिटेड को निम्नलिखित सहायक कंपनियों की गतिविधियों में तालमेल, निगरानी और समन्वय रखने, ताकि संसाधनों का बेहतरीन उपयोग हो सके और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को तैयार हालत में एकमुश्त सेवाएं

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1986 में निगमित किया गया था।

1. भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम;
2. भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद;
3. ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता;
4. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई;
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक;
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद।

2002–2003 में सभी सहायक कम्पनियों का कुल उत्पादन 830 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसेल्स लि.

भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसेल्स लिमिटेड (बी एच पी वी) का गठन 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोकेमिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूंजीगत साज–सामान की आपूर्ति के लिए किया गया था।

कम्पनी के तीन प्रभाग हैं, जिनके नाम हैं: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स डिवीजन और बॉयलर डिवीजन। विद्यमान सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए कंपनी ने

बीएचपीवी द्वारा आईओसी, हल्दिया के लिए रिएक्टर रीजेनरेटर

विश्व की प्रसिद्ध कंपनियों से तकनीकी सहायता के साथ वायु और गैस विलगन संयंत्रों के विनिर्माण, औद्योगिक बॉयलरों के डिजाईन और विनिर्माण, प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रणाली पैकेजों जैसी अनेक स्कीमों का विविधीकरण किया है। सरकार कंपनी का विनिवेश करने/संयुक्त उद्यम गठित करने के लिए संभावनाओं का पता लगा रही है। वर्ष 2002–2003 के लिए कम्पनी का उत्पादन 250 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

भारत पंप्स एंड कम्प्रैशर्स लि.

भारत पंप्स एंड कम्प्रैशर्स लिमिटेड (बी पी सी एल) की स्थापना 1970 में नैनी, इलाहाबाद में की गयी थी। कम्पनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पम्प और कंप्रेशरों की जरूरत पूरी करती है। कंपनी रूग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। कंपनी की बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार योजना पर अमल किया जा रहा है। पुनरूद्धार योजना के अनुसार सरकार ने 15.75 करोड़ रुपये की नई राशि जारी की है और 81 करोड़ रुपये का वित्तीय पुनर्गठन किया है। बीआईएफआर योजना असफल हो गई है। बीआईएफआर के निर्देश पर प्रचालन अभिकरण ने प्रबंधन बदलने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं। वर्ष 2002–2003 में कम्पनी का उत्पादन 85 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लि.

ब्रिज एंड रूप कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना बामेर लॉरी एंड कं की सहायक कम्पनी के रूप में की गयी थी। बाद में, 1978 में भारत सरकार ने 1.74 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्सा पूंजी का सीधा निवेश किया तथा यह एक सरकारी कम्पनी बन गई। इसका प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986 में पेट्रोलियम मंत्रालय से इसके नियंत्रण में आया। कम्पनी की प्रमुख गतिविधियों में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, शीतलन प्रणालियों का निर्माण, तेल शोधन संयंत्रों, उर्वरक कारखानों, रसायन संयंत्रों और एल्युमिनियम संयंत्रों आदि का यांत्रिक निर्माण कार्य शामिल है। सरकार कंपनी का संयुक्त उद्यम बनाने/विनिवेश करने के लिए

कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2002-2003 में कंपनी का कारोबार 380 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

बी एंड आर द्वारा आरंभ किए गए सड़क निर्माण कार्य के लिए इलैक्ट्रिक सेंसर के साथ पेवर-फिनिशर

रिचर्डसन एंड क्रूडास

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी) का 1973 में निजी क्षेत्र की एक इंजीनियरिंग कम्पनी से अधिग्रहण किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं। जिनमें से दो मुंबई में और एक-एक चैन्नई और नागपुर में हैं। 1987 में कम्पनी, भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी बन गई है।

कंपनी द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों में इस्पात के ढांचे, ट्रांसमिशन लाइनों के टाव, औद्योगिक मशीनरी, रसायन मशीनरी, प्रशीतलन संयंत्र आदि शामिल हैं। कम्पनी रुग्ण है और बीआईएफआर को संदर्भित है। बीआईएफआर द्वारा नवम्बर, 1995 में स्वीकृत पुनरूद्धार योजना के अनुसार सरकार ने 133 करोड़ रुपए की लागत पर वित्तीय पुनर्गठन किया है। कंपनी को अब संयुक्त उद्यम बनाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ सलाहकारों की नियुक्ति की गई है। सरकार संयुक्त उद्यम गठन इक्विटी के विनिवेश के लिए कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2002-2003 में इसका उत्पादन 65 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टी एस एल) का गठन जुलाई, 1965 में किया गया था। कम्पनी मुख्य रूप से इस्पात के भारी ढांचों, जैसे बिजली ट्रांसमिशन, संचार और टेलिविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट का निर्माण करती है और हाइड्रोकेमिकल उपकरणों, प्रेशर वाल्व आदि का उत्पादन करती है। अप्रैल, 1987 में कंपनी भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी बनी। कम्पनी रुग्णावस्था में है और बीआईएफआर को संदर्भित है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार सरकार ने 29.22 करोड़ रुपये का नया निवेश उपलब्ध कराया है और 40.26 करोड़ रुपये का वित्तीय पुनर्गठन किया है। बीआईएफआर ने पहले कंपनी को बंद करने का नोटिस जारी किया था, जिससे एक पार्टी ने कंपनी का प्रबंधन अधिग्रहण करने का प्रत्युत्तर दिया था। बीआईएफआर एक व्यवहार्य पुनर्स्थापन प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का कुल उत्पादन 30 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

टीएसएल द्वारा फाजिल्का, पंजाब में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा 302 मी. ऊंचाई वाला टीवी टावर

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.

कंपनी की गठन पहले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में अप्रैल, 1960 में हुआ था। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड फरवरी, 1967 में सरकारी कम्पनी बनी। अप्रैल, 1987 में कम्पनी, भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी बनी। इसके कार्यकलापों में हाइड्रोलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टाक), इमारतों के ढांचे, ट्रांसमिशन लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों का निर्माण और स्थापना

आदि का काम शामिल है। सरकार संयुक्त उद्यम के गठन की संभावनाओं का पता लगा रही है। संभावित बोलीदाताओं से रुचि दर्शाने के प्रस्ताव (ईओआई)) प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2002-2003 में कम्पनी का उत्पादन 20 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

टीएसपी द्वारा युगांडा को निर्यात के लिए 130 टन रोप-ड्रम हॉयस्ट

हिन्दुस्तान केबल्स लि.

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल बनाने वाली इकाई के रूप में की गयी थी। कंपनी की इकाइयां पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश तथा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है।

कंपनी व्यापक मात्रा में उन्नत दूरसंचार केबलों और तारों का उत्पादन करती है और रेलवे, रक्षा, संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

कंपनी के पुनरुद्धार की एक योजना सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत दूरसंचार विभाग के आर्डरों को सुरक्षित रखा गया है। कम्पनी के उत्पादन में पहले से पर्याप्त सुधार हुआ है, जोकि 1998-99 के 217 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001-2002 में 579 करोड़ रुपए हो गया। 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 607 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एच ई सी), रांची का गठन दिसम्बर, 1958 में किया गया था। इसका मूल उद्देश्य लोहे और इस्पात सहित खनन, धातुकर्म, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपकरणों व मशीनरी के डिजाइन तथा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसकी तीन उत्पादन इकाइयां हैं, यथा, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एच एम बी पी), हैवी मशीन टूल्स प्लांट (एच एम टी पी) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफ एफ पी) कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिपलर्स और ईओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपकरण, सी एन सी मशीन टूल्स और विशेष उद्देश्य के लिए मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और सेल्स का निर्माण करती है। यह कम्पनी रुग्ण है और बीआईएफआर को संदर्भित है। बीआईएफआर द्वारा 1996 में स्वीकृत पुनरूद्धार योजना के अनुसार सरकार ने 190 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 371.51 करोड़ रुपये का वित्तीय पुनर्गठन किया है। तथापि, कंपनी स्वीकृत योजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है। बीआईएफआर के निदेशानुसार तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। परामर्शदाता की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। वर्ष 2002-2003 में कम्पनी का उत्पादन 230 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

एच एम टी लि. (ट्रैक्टर प्रभाग सहित धारक कंपनी)

एच एम टी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना 1953 में हुई थी। यह कंपनी मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी का उत्पादन करने में लगी है। इसकी देश भर में अनेक उत्पादन इकाइयां हैं।

कंपनी पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटा उठा रही है। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन योजना में व्यवसाय समूहों को अलग-अलग सहायक कंपनियों में बदलने और इस सहायक कंपनियों का विनिवेश करके संगठनात्मक पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है। कंपनी का एचएमटी लि. के रूप मे पुनर्गठन किया गया है, जबकि धारक कंपनी के पास ट्रैक्टर व्यवसाय रखा गया है और अन्य

व्यवसाय समूहों को सहायक कंपनियों के रूप में विभाजित किया गया है यथा; एचएमटी मशीन टूल्स लि., एचएमटी वाचेज लि. और एचएमटी चिनार वाचेज लि.। इसके अलावा, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लि. हैं तथा एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लि. हैं।

एचएमटी मशीन टूल्स लि., एचएमटी वाचेज लि., एचएमटी चिनार वाचेज लि. और एचएमटी बियरिंगंस लि. के विनिवेश/संयुक्त उद्यम गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सहायक कंपनियों का विनिवेश/संयुक्त उद्यम गठन का कार्य पूरा होने के बाद एचएमटी(आई) लि. और एचएमटी (धारक कं.) के विनिवेश/संयुक्त उद्यम गठन का कार्य दूसरे चरण में आरंभ किया जाएगा।

एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने मैसर्स मोटोकोव के साथ तकनीकी सहयोग में 1971 में अपने प्रचालन आरंभ किए थे। एचएमटी ने आरंभ में प्रचालन पिंजौर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में 25 हार्सपावर के ट्रैक्टर के विनिर्माण से आरंभ किया था। गत वर्षों में इसने 75 हार्सपावर से 225 हार्सपावर के ट्रैक्टर विकसित किए हैं। कंपनी कृषक समुदाय के प्रयोग वाली श्रृंखला के ट्रैक्टरों के बाजार में अपनी अग्रता प्राप्त करने में सफल रही है।

इस समय कंपनी की ट्रैक्टर विनिर्माण करने वाली भारत में तीन इकाइयां क्रमश हरियाणा पिंजौर में, पंजाब मोहाली में और आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित हैं। इसके पास वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र हैं।

एचएमटी का ट्रैक्टर व्यवसाय समूह राष्ट्रीय स्तर के अनेक उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। यह केमा, नीदरलैंडस द्वारा आईएसओ-9001 के लिए प्रमाणित है।

इसके आंतरिक विपणन संगठन में 17 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 स्टॉकयार्ड और 300 से अधिक विक्रेता शामिल हैं, जोकि देशभर में फैले हुए हैं। एचएमटी ट्रैक्टर समूह को 40 सहायक इकाइयों से अच्छा सहयोग मिलता है। एचएमटी ने अपनी स्थापना से आरंभ होकर भारत और विदेश में 3,60,000 से अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन और विपणन किया है।

ट्रैक्टरों सहित एचएमटी धारक कंपनी का उत्पादन वर्ष 2002-2003 के दौरान 263 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

एचएमटी द्वारा विकसित एचएमटी 4922 ट्रैक्टर

एचएमटी मशीन टूल्स लि.

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एचएमटी लि. ने "एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड" नामक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का 1999 में निगमन किया था।

एच एम टी - एमटी लि. की पांच स्थानों पर अपनी विनिर्माण इकाइयां हैं, जोकि मशीन टूल्स के किसी विशेष समूह में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। इसका बिक्री और सेवा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। एचएमटी-एमटी लि. की सभी विनिर्माण इकाइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 250 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है।

एचएमटी वॉचेज लि.

भारत में सर्वप्रथम घड़ियों बनाने वाले एचएमटी लि. ने "एचएमटी वाचेज लिमिटेड" नामक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का 1999 में निगमन किया था। यह मेकेनिकल और क्वार्टज़ एनालॉग घड़ियां बनाती हैं।

कलाई घड़ियों का विनिर्माण जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग के अंतर्गत वर्ष 1962 में एचएमटी की विविधीकरण रणनीति के एक भाग के रूप में बंगलौर में आरंभ किया गया था।

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की बंगलौर तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं, जबकि विपणन मुख्यालय बंगलौर में है। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणन प्राप्त है।

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के सभी वर्गों, सस्ती से मंहगी तक और नौजवानों से लेकर बड़ों तक के लिए सेवा प्रदान करती है। एचएमटी ब्रांड की भारतीय बाजार में काफी अधिक ब्रांड हिस्सेदारी है। इसके ब्रांड को देश में अग्रणी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में भारतीय ब्रांडों में लगातार सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। एचएमटी ब्रांड घरेलू बाजार में प्रमुख घड़ी विक्रेताओं के बीच लगातार मुख्यधारा का ब्रांड बना हुआ है।

एचएमटी द्वारा जारी कलाई घड़ी के कुछ मॉडल

एचएमटी चिनार वाचेज लि.

भारत में सर्वप्रथम घड़ियां बनाने वाली एचएमटी लि. ने "एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड" नामक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का 2000 में निगमन किया था। यह पुरूषों के लिए मेकेनिकल घड़ियां बनाती है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड में जम्मू में पंजीकृत कार्यालय सहित जम्मू में एकत्रण (असेम्बली) इकाई और श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर) में एक विनिर्माण इकाई शामिल हैं।

एचएमटी चिनार वाचेज लि. की उत्पाद श्रृंखला में 13 मॉडल हैं। एचएमटी घड़ियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता उपभोक्ता के लिए प्रमुख आकर्षण और बिक्री की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। एचएमटी चिनार वाचेज लि. अपने उत्पादों का विपणन एचएमटी लि. की एक अन्य संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी वाचेज लि. के व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से करता है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के पास प्रतिवर्ष 5 लाख घड़ियों के विनिर्माण की क्षमता है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 3.70 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

प्रागा टूल्स लि.

प्रागा टूल्स लि. (पीटीएल), सिकन्दराबाद का गठन मूलत: एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में 1943 में किया गया था। यह कंपनी 1959 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। फरवरी, 1988 में जब इसकी 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी एच एम टी लिमिटेड के नाम हस्तांतरित की गयी और यह उसकी सहायक कम्पनी बन गयी।

यह कंपनी विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स अर्थात सी एन सी कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सी एन सी मिलिंग मशीन, थ्रेड रॉलिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन, विभिन्न मॉडलों की सी एन सी जिग बोरिंग मशीन आदि का उत्पादन करती रही है। कम्पनी रुग्ण है और बीआईएफआर को संदर्भित है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कम्पनी का उत्पादन 10 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

एच एम टी (बियरिंग) लि.

एच एम टी (बियरिंग) लिमिटेड (जिसका पुराना नाम इंडो निप्पोन प्रेसिजन बियरिंग था) की स्थापना 1964 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गयी थी। 1981 में यह एच एम टी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। वर्ष 2002-2003 के दौरान कम्पनी का उत्पादन 35 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

एच एम टी (इंटरनेशनल) लि

एच एम टी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में एच एम टी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गयी थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में यंत्र और उपकरण, घड़ियां और इनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें अफ्रीका, रूस, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है। वर्ष 2002-2003 में कंपनी का करोबार 71 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आई एल के) की स्थापना 1964 में की गयी थी। इसकी तीन उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान) और पलाक्कड़ (केरल) में हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी मै. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्सट्रूमेंटस लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधारित एवं डिजीटल वितरित नियंत्रण प्रणाली, उन्नत ट्रांसमिटरों, दोष सहाय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेत प्रणालियों और दूरसंचाार उपस्करों के विनिर्माण के कार्य में लगी है।

कंपनी रूग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर ने मार्च, 1999 में एक पुनरूद्धार पैकेज स्वीकृत किया है, जिस पर अमल किया जा रहा है। पुनरूद्धार योजना के अनुसार, सरकार ने 66 करोड़ रुपए की नई राशि जारी कर दी है और 42.98 करोड़ रुपए का वित्तीय पुनर्गठन किया है। स्वीकृत पुनरूद्धार योजना के अनुसार आईएल के तीन प्रभागों यथा; पलाक्कड़ में कंट्रोल वाल्व, कोटा में डी डी सी और जयपुर में पावर इलैक्ट्रोनिक्स (यू पी एस) के लिए रूचि दर्शाने (ई ओ आई) के वास्ते बोलियां आमंत्रित की गई थीं। कंपनी की केवल पलाक्कड़ इकाई के लिए रूचि दर्शाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जबकि डीडीसी और पावर इलैक्ट्रोनिक्स के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी की पुनरूद्धार योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के बाद सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन एक्सचेंजों की आवश्यकता के 10 प्रतिशत की सीमा तक आदेशों के आरक्षण का अनुमोदन कर दिया है। सरकार आईसीवीएल के संबंध में विनिवेश करने/ संयुक्त उद्यम गठित करने के प्रयास कर रही है। शेयरधारक करार/शेयर क्रय करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 152.50 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लि.

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर ई आई एल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के संयुक्त उपक्रम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टर (ई.एम.टी.) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों, डेरियों, दुग्ध शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी ने सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपनी उत्पादन रेंज का विविधीकरण किया है। अपने चमकदार कार्य-निष्पादन के कारण इस सरकारी उद्यम ने 'मिनिरत्न' का स्तर प्राप्त किया है। पुनर्गठन प्रयास के एक भाग के रूप में कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के वास्ते कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। वर्ष 2002-2003 में कंपनी का उत्पादन 31.63 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

खेड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में आरईआईएल द्वारा स्थापित सौर विद्युत संयंत्र का एक दृश्य

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एन आई एल) का गठन जून, 1957 में उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के अधीन एक विभागीय कार्यशाला नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की सम्पत्तियों और देयताओं

के अधिग्रहण से हुआ था। कंपनी रात में देखने में काम आने वाले उपकरणों सहित गैस मीटर, कैमरा, प्रैशर व वैक्यूम गेज सहित सर्वेक्षण के लिए गई प्रकार के आप्टिकल और आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन और व्यापार करती है। कंपनी रुग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर द्वारा नवम्बर, 1999 में स्वीकृत पुनरूद्धार योजना के अनुसार, सरकार ने निधियों के लिए निवेश के रूप में 17.96 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तथापि, कंपनी का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक है। कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम के गठन की संभावना का पता लगाने के लिए प्रयास आरंभ किए गए है। वर्ष 2002-03 में कंपनी का उत्पादन 6.35 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

स्कूटर्स (इंडिया) लि.

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एस आई एल) का गठन सितम्बर, 1972 में हुआ था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का उत्पादन होता है। कंपनी रुग्ण होने के कारण बीआईएफआर को संदर्भित की गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और लगातार पिछले तीन वर्षों में कंपनी ने लाभ दर्शाया है। कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार होने से यह बीआईएफआर के विचार क्षेत्र से बाहर आ गई है। वर्ष 2002-2003 में कंपनी का उत्पादन 127.61 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि.

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी ओ जी एल) की स्थापना नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड से दुर्गापुर स्थित ऑप्थाल्मिक ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर अप्रैल, 1972 में की गई थी। कंपनी ऑप्थल्मिक ब्लैंक फ्लिंट बटन, आप्टिकल ग्लास, खिड़कियों के लिए विकिरण रोकने वाले शीशे और रक्षा, परमाणु और अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष किस्म का आप्टिकल ग्लास बनाने वाली कंपनी है। कंपनी रुग्ण हो चुकी है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। प्रचालन एजेंसी द्वारा प्रचालित मसौदा पुर्नस्थापन योजना की जांच की जा रही है। इस बीच, कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम के गठन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कारवाई आरंभ कर दी गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान कंपनी का उत्पादन 2.65 करोड़ रुपये का अनुमान है।

सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी सी आई) का गठन जनवरी, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां कार्य कर रही हैं, जो मध्य प्रदेश में मन्धार, अकलतारा और नयागांव; कर्नाटक में कुरकुंटा; असम में बोकाजन; हिमाचल प्रदेश में राजबन; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तेंदूर तथा हरियाणा चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है।

धन की अत्यंत कमी, आधारभूत ढांचे, खास तौर पर बिजली की कमी के कारण कंपनी के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसकी 10 में से 7 इकाइयां विभिन्न कारणों से प्रचालन में नही हैं। कंपनी रुग्ण अवस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्रचालन एजेंसी ने एक मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति कर दी है, ताकि पूरी सी सी आई को मई, 2003 तक चालू रूप में संस्था या इकाइयों को अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से बेचने का कार्य पूरा किया जा सके।

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि.

1970 में गठित हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) कागज, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है।

एच पी सी एक धारक कंपनी है और इसकी 2 सहायक कंपनियां और 2 प्रमुख समन्वित कागज व लुगदी मिलें हैं। इनके नाम हैं:-

सहायिकाएं:

1. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एच एन एल)
2. नागालैंड पल्प एवं पेपर कंपनी लिमिटेड (एन पी पी सी)*

इकाइयां:

1. नौगांव पेपर मिल्स (एन पी एम)
2. कछार पेपर मिल्स (सी पी एम)

वर्ष 2002-03 के दौरान कंपनी (एनपीएम तथा सीपीएम) का उत्पादन 542.17 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

* अपनी पिछली सुनवाई में बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है।

एचपीसी का कछाड़ कागज कारखाना

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एन पी पी सी) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है। एच पी सी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार 5.22 प्रतिशत शेयरों की स्वामी है। वित्तीय पुनर्गठन के कारण कंपनी बीआईएफआर के दायरे से बाहर आ गयी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति, आधारभूत ढांचे की कमी और बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण पुनरुद्धार योजना पर अमल न हो सकने से यह पुन: रुग्ण हो गई। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एच एन एल) को मूलत: एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था। बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एच पी सी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायिका में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के निर्माण में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। कंपनी ने 52.20 करोड़ की लागत से एक डी-इंकिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना आरंभ की है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है और वन्य संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। संयुक्त उद्यम का गठन करने के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। संभावित बोलीदाताओं से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पहले एसएचए/एसपीए के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी का उत्पादन 214.08 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लि.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एच पी एफ) की स्थापना 1960 में चलचित्र उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा बलों और फोटोग्राफरों को क्रमश: फोटोग्राफिक फिल्म, एक्स-रे फिल्म और विशेष फोटोग्राफिक सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। कंपनी के दो उत्पादन संयंत्र-मुख्य फैक्ट्री ऊटकमंड में और एक संयंत्र चेन्नई के पास अम्बातूर में हैं। एचपीएफ ने 1967 में उत्पादन आरम्भ किया। कंपनी समन्वित उत्पादन और जम्बों कन्वर्जन, दोनो का काम करती है। समन्वित उत्पादन से बनायी जाने वाली चीजों में सिने फिल्म पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म, फोटोग्राफी का कागज और शौकिया फोटोग्राफी करने वालों के लिए श्वेत-श्याम फिल्मों के रॉल शामिल है। कंपनी ने एक परियोजना बनायी है, जिसके अंतर्गत पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्म्स का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी रुग्ण है तथा बीआईएफआर को संदर्भित है। वर्ष 2002-03 के दौरान कंपनी का उत्पादन 30 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.

वर्ष 1959 में स्थपित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एच एस एल) अपनी तीन इकाइयों खारागोडा (गुजरात), मंडी (हिमाचल प्रदेश) और रामनगर (उत्तर प्रदेश) में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का उत्पादन करती है। कंपनी रुग्णावस्था में होने के कारण बीआईएफआर के विचाराधीन है। विनिवेश मंत्रालय द्वारा कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के वास्ते प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान इसका उत्पादन 7.71 करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है।

सांभर साल्ट्स लि.

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एस एस एल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी प्रदत पूंजी एक करोड़ रुपये है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और बाकी 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अंशदान किया गया है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल का नमक बनाने के साथ नमक पर आधारित रसायनों का निर्माण कर रही है। कंपनी को संयुक्त उद्यम में बदलने के लिए विनिवेश मंत्रालय द्वारा प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। 2002-03 के दौरान कंपनी का उत्पादन 7.38 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

नेपा लि.

नेपा लिमिटेड (एन ई पी ए) को पहले नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्तूबर, 1949 में राज्य सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस तरह यह केन्द्र सरकार का सरकारी उद्यम बन गई। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रुग्णवस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया और 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक इक्विटी की रणनीतिक बिक्री के अलावा सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इत्यादि का अनुमोदन कर दिया है। कंपनी का विनिवेश/संयुक्त उद्यम बनाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं।

वर्ष 2002-03 में इसका उत्पादन 72.41 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.

टायर कापोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 1984 में निगमित किया गया था, जिसमें दो राष्ट्रीयकृत रुग्ण कंपनियों, मै. इन्चेक टायर्स लिमिटेड और मै. नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड को निहित कर दिया गया था। इस कंपनी की तीन प्रचालन इकाइयां इस प्रकार हैं: (1) काकीनाड़ा में टायर डिवीजन; (2) टांगड़ा में औद्योगिक रबड़ उत्पाद डिवीजन; और (3) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में रीक्लेम्ड रबड़ इकाई। इसके द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों में मोटर वाहनों के टायर और ट्यूब, नायलॉन कन्वेयर बैल्ट, होस पाइप, वी बैल्ट और फैन बैल्ट आदि शामिल हैं। बाद में चेकोस्लोवाकिया की टेक्नो-एक्सपोर्ट के तकनीकी सहयोग से 6.31 लाख टायर और ट्यूब के निर्माण की वार्षिक क्षमता वाली एक आधुनिकीकरण तथा विस्तार परियोजना पूरी की गयी। कंपनी रुग्ण है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। उपयुक्त प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। कंपनी को संयुक्त उद्यम में बदलने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं। 2002-2003 में कंपनी का उत्पादन 105.60 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भारत लैदर कारपोरेशन लि.

भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड (बी एल सी) का गठन मार्च, 1976 में हुआ था, ताकि कंपनी चमड़े के सामान और जूतों आदि की खरीद और बिक्री जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा प्रोत्साहन और विकास संबंधी कार्य कर सके। कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के प्रयास असफल रहे हैं। इस बीच, कंपनी के सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ ले लिया है। कंपनी के सभी प्रचालन बंद कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद करने पर विचार किया जा रहा है।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसका गठन 1970 में हुआ था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनात्मक इंजीनियरी सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2001 में कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और लाभ अर्जित किया है। कंपनी को संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में बदलने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं।

रुचि दर्शाने के प्रस्ताव (ई ओ आई) प्राप्त हुए हैं और एसपीए/एसएचए को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2002–03 में कंपनी का कारोबार 417.84 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एन आई डी सी) की स्थापना सरकार ने 1954 में की थी। कंपनी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना, औद्योगिक बस्तियों, जल आपूर्ति एवं शोधन, पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, औद्योगिक परियोजनाओं और कम्प्युटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास के क्षेत्र में परामर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराती रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रही है। चूंकि, यह कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए इसे बीआईएफआर को संदर्भित नहीं किया जा सकता। कंपनी को संयुक्त उद्यम में बदलने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुना है। कंपनी को बंद करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्रवाई आरंभ की गई है।

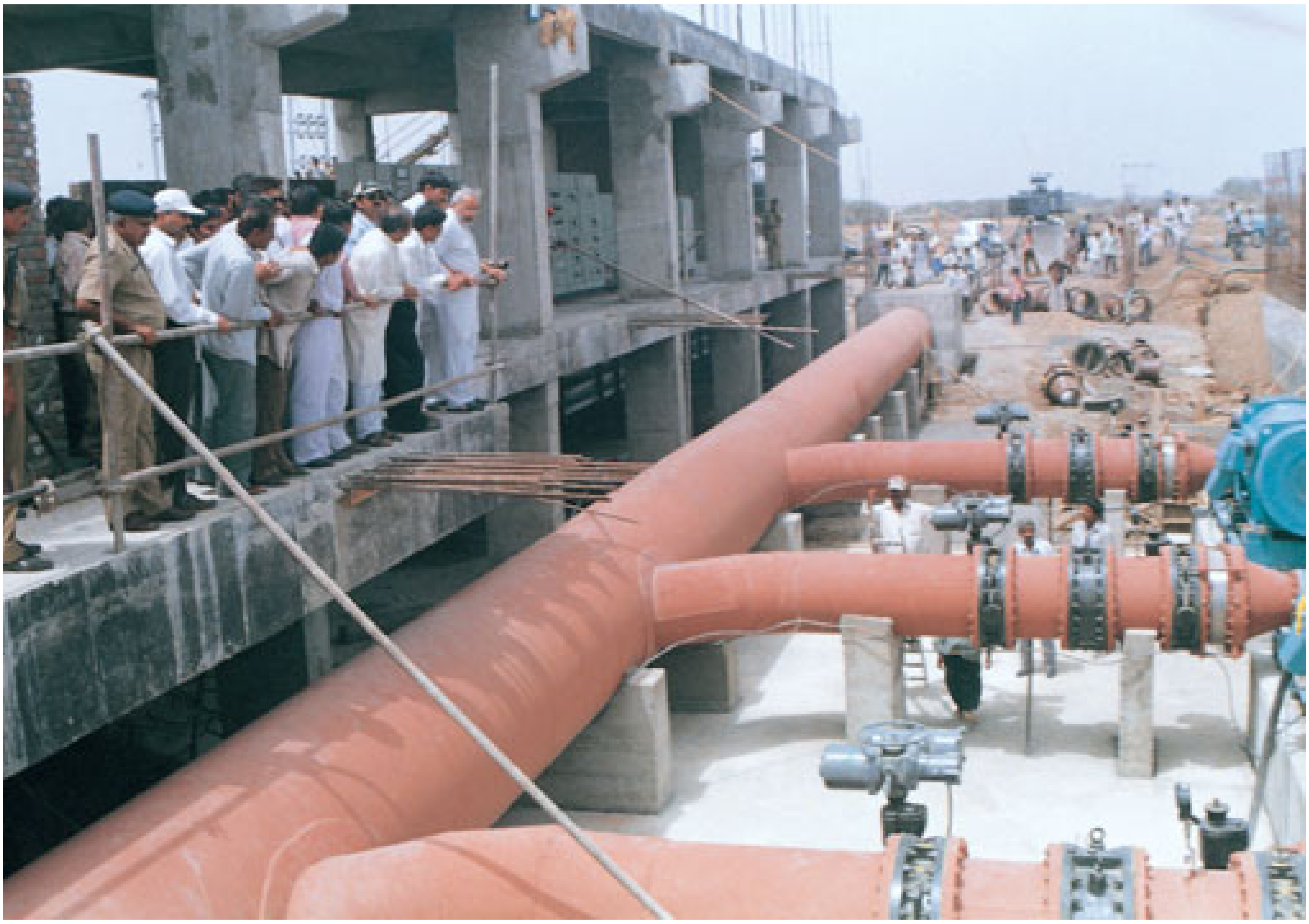

ईपीआई द्वारा गुजरात में आरंभ की गई सरदार सरोवर नहर आधारित पेय जल आपूर्ति परियोजना

भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र

भारी विद्युत उद्योग

''भारी विद्युत उद्योग'' में वे औद्योगिक इकाइयां आती हैं, जो बिजली पैदा करने, उसके पारेषण, वितरण और उपयोग में काम आने वाले बड़े संयंत्रों और मशीनों का निर्माण करती हैं। इनमें टर्बो–जेनरेटर, बॉयलर्स, विभिन्न प्रकार के टरबाइन, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, स्विचगियर्स और अन्य ऐसे ही उपकरण शामिल हैं।

देश में भारी विद्युत उद्योग द्वारा विनिर्मित अधिकतर उत्पादों में शामिल विद्युत उत्पादन एकक, बिजली की मोटरों, ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों आदि इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल भारतीय अर्थवयवस्था के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इनका इस्तेमाल जिन प्रमुख क्षेत्रों में होता है, उनमें परमाणु बिजलीघर सहित बिजली पैदा करने वाली करोड़ों रुपये की लागत वाली परियोजनाएं, पैट्रोरसायन परिसर, रासायनिक संयंत्र, एकीकृत इस्पात संयंत्र, अलौह धातु इकाइयां आदि शामिल हैं। यह उद्योग वर्तमान प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने में जुटा है। परिणामत: भारत उन कुछेक देशों में से है, जिनके पास निर्यात बाजारों के लिए टर्नकी आधार पर जटिल परियोजनाए लेने का मजबूत आधार है। उद्योग किसी भी वस्तु का विनिर्माण करने के लिए स्वतंत्र है।

उद्योग की वर्तमान स्थापित क्षमता 4500 मेगावाट ताप बिजली, 1345 मेगावाट पन बिजली और करीब 250 मेगावाट गैस आधारित बिजली पैदा करने के उपकरणों का हर वर्ष निर्माण करने की है और आवश्यकता तथा अपनी क्षमता के अनुसार विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस उद्योग ने देश में परमाणु बिजली संयंत्र के लिए उपकरणों का निर्माण करने का भी मजबूत विनिर्माण आधार स्थापित किया है। देश की बिजली पैदा करने की क्षमता में करीब 66 प्रतिशत घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।

भारी विद्युत उद्योग 400 केवी एसी और हाई वोल्टेज डीसी तक पारेषण और वितरण में काम आने वाले उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम है। भारतीय उद्योग ने 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफार्मरों की अगली उच्चतर वोल्टेज प्रणाली में परिषण के उन्नयन, रिएक्टरों, सीटी, सीवीटी, बुशिंग और इंसुलेटरों से संबंधित कार्य हाथ में लिया है। इस्पात संयंत्रों, पेट्रो–रसायन परिसरों और ऐसे ही अन्य भारी उद्योगों में काम आने वाली बड़ी विद्युत मोटरों का निर्माण भी देश में ही किया जा रहा है।

घरेलू भारी विद्युत उपकरण विनिर्माता उत्पाद–डिजाइन और विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की गतिविधियों का लाभ उठा रहे हैं। उद्योग ने फ्लैक्सीबल एसी पारेषण (फैक्टर) और अन्य विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स परियोजनाओं के विकास का कार्य आरंभ किया है। भेल फैक्ट्स और नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर) की शुरुआत कर चुका है।

भारी विद्युत उद्योग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट नीचे दी गई हैं:–

टरबाइन और जेनरेटर सेट

विभिन्न प्रकार के टरबाइनों, जैसे औद्योगिक टरबाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टरबाइनों के विनिर्माण की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 7000 मेगावाट से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल, जिसकी स्थापित क्षमता 6000 मेगावाट सबसे अधिक है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी ऐसी इकाइयां हैं, जो बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए स्टीम और हाइड्रो टरबाइनों का निर्माण कर रही है। भेल के निर्माण दायरे में 500 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले स्टीम टरबाइन शामिल हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाकर 660 मेगावाट करने की योजना है। भेल 255 मेगावाट (आई एस ओ) तक क्षमता वाली गैस टरबाइन बनाने की भी क्षमता रखता है।

भेल द्वारा चीन को निर्यात किया गया 123 मेवा. गैस टरबाइन (फ्रेम 9ई)

भारत में विनिर्मित एसी जेनरेटर अंतरराष्ट्रीय एसी जेनरेटरों के समान हैं, जो निष्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करते हैं। घरेलू विनिर्यात 0.5 केवीए से 25000 केवीए और ऊपर विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के साथ एसी जेनरेटर के विनिर्माण में सक्षम है।

बॉयलर

भेल देश में बॉयलर बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है और कोयला, लिग्नाईट, तेल, प्राकृतिक गैस या इन ईंधनों के संयोजन के प्रयोग द्वारा 30 से 500 मेवा. के बॉयलरों के विनिर्माण और 1000 मेवा. इकाई आकार के सुपर (क्रिटीकल) मानदंड वाले बॉयलर बनाने की भी क्षमता रखती है। इस समय भेल बॉयलरों के कुल उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग बॉयलरों की देशी आवश्यकता/मांग पूरी करने की क्षमता रखता है।

ट्रांसफार्मर्स

घरेलू ट्रांसफार्मर उद्योग भली-भांति स्थापित है और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। उद्योग आरईसी रेटिंग के 25,53,100 केवीए और अतिरिक्त 400 केवी, 600 एमवीए की हाई वोल्टेज रेंज के ट्रांसफार्मरों सहित बिजली पैदा करने और वितरण संबंधी ट्रांसफार्मर बनाने की क्षमता रखता है। अर्थिंग भट्टियों, रेक्टिफायर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपीटेटर्स, फ्रेट लोको आदि के लिए आवश्यक विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर और सीरीज एंड शंट रिएक्टर्स तथा 500 केवी तक के एचवीडीसी ट्रांसमिशन का विनिर्माण भी देश में ही हो रहा है। उद्योग, इस देश के बिजली क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भली-भांति तैयार है।

भारतीय उद्योग के लिए निर्यात अवसरों में भी वृद्धि हुई है। अनेक ट्रांसफार्मर विनिर्माता पश्चिमी देशों और अमरीका के कुछ हिस्सों में भी अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

स्विचगियर और कंट्रोल गियर

भारत में बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम से लेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड (एसएफ 6) तक सभी रेंजों के सर्किट ब्रेकरों का निर्माण ग्राहकों की खास जरूरतों के अनुरूप किया जाता है। निर्मित उत्पादों के रेंज में 240 वोल्ट से 800 वोल्ट तक की समग्र वोल्टता रेंज शामिल है। स्विचगियर और कंट्रोलगियर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स (एमसीबी), एयर सर्किट ब्रेकरों, स्विचों, रीवायरबेल फ्यूजों और हाई रपचर कैपेसिटी (एच आर सी) फ्यूजों तथा उनके संबंधित फ्यूज बेस, होल्डर्स और स्टार्टर्स का निर्माण ग्राहकों की जरूरतों और मानक आकार के अनुसार किया जाता है। बिजलीघरों, लोड डिस्पैच केन्द्रों, प्रमुख रिसीविंग केन्द्रों और औद्योगिक परिसरों के लिए माइक्रोप्रोसेसर और कम्प्यूटर-नियंत्रित मोटर कंट्रोल सेंटर, डिस्ट्रिब्यूशन पैनल और व्यापक नियंत्रण प्रणालियां भी उपलब्ध हैं।

डिजायन और इंजीनियरी के क्षेत्र में उद्योग प्रतिस्पर्धी हैं, क्योंकि देश में उपलब्ध शिल्प संबंधी सैट सस्ते उपलब्ध हैं।

विद्युत भट्ठी

विद्युत भट्ठियां दो प्रकार की हैं (i) इंडक्शन भट्ठियां, हीटिंग उपकरण जिसमें इंडक्शन हीटिंग उपकरण भी शामिल हैं; और (ii) आर्क भट्ठियां। इलेक्ट्रिकल भट्ठियों का इस्तेमाल फोर्जिंग और फांउडरी, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल आदि धात्वीय और इंजीनियरी उद्योगों में किया जाता है। इन उपकरणों के उत्पादन के लिए समुचित क्षमता हासिल कर ली गई है।

शंटिंग लोकोमोटिव

शंटिंग लोकोमोटिव का इस्तेमाल रेलवे, स्टील प्लांटो, थरमल पावर प्लांटों आदि द्वारा स्थानीय/आंतरिक परिवहन सुविधाओं के लिए किया जाता है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए भी प्र्याप्त

निर्माण क्षमता हासिल कर ली गई है। भेल अन्य चीजों के साथ-साथ ऐसे लोकोमोटिवों का निर्माण करती है।

टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता हिस्से-पुर्जों, अतिरिक्त एवं अनुषंगी उपकरणों सहित यार्न/फैब्रिक की छंटाई, रस्सी बनाने, प्रसंस्करण और बुनाई के लिए अपेक्षित वस्त्र मशीनरी का विनिर्माण कर रहे हैं। करीब 600 इकाइयां हैं, जो मशीनरी, हिस्से-पुर्जों और अनुषंगी उपकरणों के विनिर्माण में लगी हैं तथा इनमें से करीब 100 इकाइयां ऐसी हैं, जो पूरी तरह टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माण में लगी हुई हैं।

लक्ष्मी मशीन वर्क्स द्वारा उत्पादित आटो डोफर 1200 स्पिंडल्स सहित रिंग फ्रेम एलआर6 एएक्स

1500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और 3600 करोड़ रुपए की स्थापित वार्षिक क्षमता के साथ उनके गत 3 वर्ष के उत्पादन एवं निर्यात का ब्योरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1999-2000	1111	447
2000-2001	1308	427
2001-2002 (अनुमानित)	1073	427

सीमेंट मशीनरी उद्योग

विनिर्माता ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि-टैक्नोलॉजी के आधार पर 7500 टीपीडी क्षमता वाले पूर्ण सीमेंट प्लांटों का विनिर्माण और उनकी आपूर्ति कर रहे हैं। आधुनिक सीमेंट प्लांटो का डिजाइन यह ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय ने लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पूर्ण ऊर्जा की खपत के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पूर्ण सीमेंट प्लांट मशीनरी के निर्माण के लिए वर्तमान में संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां काम कर रही हैं। उद्योग सीमेंट मशीनरी की घरेलू मांग पूरी करने में पूरी तरह सक्षम है। वर्तमान स्थापित क्षमता का मूल्य 600 करोड़ रुपए /प्रतिवर्ष आंका गया है। वर्ष 2002-2001 और 2001-2002 के दौरान उत्पादन क्रमशः 395.45 करोड़ रुपए और 274.57 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2001-2002 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 0.42 करोड़ रुपए और 4.38 करोड़ रुपए मूल्य का रहा। उद्योग मांग की कमी का सामना कर रहा है, जिसके कारण क्षमता का कम उपयोग हो रहा है।

चीनी मशीनरी उद्योग

चीनी उद्योग मशीनरी के घरेलू निर्माता अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खास महत्व रखते हैं। यह उद्योग 10,000 टी सी डी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक क्षमता वाले अत्याधुनिक डिजाइन के चीनी प्लांटों के विनिर्माण की क्षमता रखता है। संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ण चीनी प्लांट और हिस्से-पुर्जों का विनिर्माण करने वाली 27 इकाइयां हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 200 करोड़ रुपए है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उत्पादन क्रमशः 208.46 करोड़ रुपए और 170.63 करोड़ रुपए रहा।

विनिर्माण अवधारणा से लेकर चालू करने तक के नवीनतम डिजायन के पूरे संयंत्र का डिजायन और विनिर्माण कर सकते हैं। उद्योग घटती हुई मांग का सामना कर रहा है।

2001-2002 के दौरान इस उद्योग का आयात और निर्यात क्रमशः 3 लाख रुपए और 253 लाख रुपए रहा।

रबड़ मशीनरी उद्योग

रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। ये मशीनें मुख्य रूप से टायर/ट्यूब उद्योग में काम आती है। देश में निनिर्मित उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसिज, ट्यूब सप्लाइसर, ब्लेडर क्योरिंग प्रेसिज, टायर, माउल्डस, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नर सर्विस, बायर्स, कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल है।

उच्च गति वाले केलोडरिंग लाइन विशेषकर हैवी अर्थमूविंग उपस्कर के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में अंतर है।

विगत में यह उद्योग कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्ध के बीच टायर/ट्यूब क्योरिंग प्रेसिज, ट्यूब सप्लाइर्स, आदि के निर्यात ऑर्डर हासिल करता रहा है। 2001-2002 के दौरान इस उद्योग का आयात और निर्यात क्रमश: 11.35 करोड़ रुपए और 11.04 करोड़ रुपए रहा।

सामग्री संचालन उपकरण उद्योग

इस उद्योग के तहत विनिर्मित उपकरणों में क्रशिंग और स्क्रीनिंग प्लांट, कोयला/अयस्क/राख हैंडलिंग प्लांट सम्बद्ध उपकरण जैसे स्टेकर, रीक्लेयर, शिप लोडर/अनलोडर वैगन टिप्पलर, फीडर आदि शामिल है, जो कोयला, सीमेंट, बिजली, बंदरगाह, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्र जैसे बुनियादि उद्योग की बढ़ती एवं तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए उत्पादन क्रमश: 498.53 करोड़ रुपए और 174.87 करोड़ रुपए था। संगठित क्षेत्र की इकाइयों के अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां सामग्री प्रहस्तन उपकरण और उनके पुर्जे बनाने के काम में लगी है। 2001-2002 के दौरान इस उद्योग का आयात और निर्यात क्रमश: 124.10 करोड़ रुपए और 22.09 करोड़ रुपए मूल्य का रहा। यह उद्योग कमोबेश घरेलू मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम हैं।

लुगदी और कागज मशीनरी

संगठित क्षेत्र के अंतर्गत लुगदी और कागज मशीनरी बनाने वाली 78 इकाइयां हैं। इनकी स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनों का विनिर्माण करने की है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए उत्पादन क्रमश: 70.84 करोड़ रुपए और 60.62 करोड़ रुपए था।

स्वदेशी उद्योग भली-भांति स्थापित है और 10 टीपीडी से 300 टीपीडी क्षमता के प्लांट उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिनमें

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में स्थापित कागज मशीन का दृश्य

लुगदी तैयार करने, स्टॉक तैयार करने, फिनिशिंग आदि सुविधाओं से संबंध उपकरण शामिल हैं। देशी उद्योग टर्नकी आधार पर मिलने वाले ऑर्डर पूरे करने की स्थिति में भी हैं। 2001-2002 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 95.15 करोड़ रुपए और 18.69 करोड़ रुपए मूल्य का रहा।

ऑयल फील्ड उपकरण

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया के जारी रहते उद्योग को सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे तेल की खोज, उत्पादन, शोध्न और विपणन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप ऑयल फील्ड और संबंधित उपकरणों की मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है। इनका उपयोग ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा चार्टर किराये के आधार पर किया जाता है।

घरेलू विनिर्माता तटीय खुदाई के लिए ड्रिलिंग रिग्स का विनिर्माण कर रहे हैं। अपतटीय ड्रिलिंग, जैसे जैक-अप रिग्स का देश में विनिर्माण नहीं किया जाता। तथापि, अपतटीय प्लेटफार्मों और अन्य प्रौद्योगिकीय ढांचों का स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादकों में भेल, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक और बर्न एंड कम्पनी शामिल हैं।

प्रिंटिंग मशीनरी

प्रिंटिंग मशीनरी को मोटे तौर पर तीन वर्गों में रखा जा सकता है: प्रिंटिंग से पहले, पिंटिंग के दौरान और प्रिंटिंग के बाद काम वाले उपकरण। विश्व के प्रमुख निर्माताओं द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास प्रयासों के फलस्वरूप प्रिंटिंग एक शिल्पोन्मुखी गतिविधि से बड़े पैमाने के यंत्रीकृत, स्वचालित और सुचारू

उद्योग में रूपान्तरित हो चुका है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी विषयक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान रूझान अब कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों, विशेषकर प्रिंटिंग से पहले काम आने वाले उपकरणों और प्रिंटिंग मशीनों के संचालन में कम्प्यूटरों का इस्तेमाल करने की ओर है। वर्तमान में देश में 70 ऐसे विनिर्माता हैं, जो प्रिंटिंग और सम्बद्ध उपकरणों के निर्माण में लगे हैं, जिनमें से 21 संगठित क्षेत्र के अंतर्गत हैं। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उत्पादन क्रमश: 145.09 करोड़ रुपए और 229.35 करोड़ रुपए रहा। विनिर्मित उपकरणों की वर्तमान रेंज में मध्यम गति की एकल और बहुरंगी शीटफेड और वेबफेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें, रोटोग्रेवर/फ्लेक्सोग्रेवर, रोटरी प्रिंटिंग मशीनें और सादी/सेमिऑटोमैटिक प्लेट मेकिंग, बाइंडिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग मशीनें शामिल हैं। देश अधिकतर प्रिंटिंग पूर्व उपकरणों और स्वचालित बाइंडिंग उपकरणों के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए प्रौद्योगिकी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2001-2002 वर्ष के दौरान प्रिंटिंग और सम्बद्ध अपकरणों का निर्यात और आयात क्रमश: 322.59 करोड़ रुपए और 110.58 करोड़ रुपए मूल्य का रहा।

धातुकर्मीय मशीनरी

धातुकर्मीय मशीनरी के अंतर्गत मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग साइज रिडॅक्शन, स्टील प्लांट उपकरण, फाउन्डरी उपकरण और भट्ठियां शामिल हैं। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत 39 इकाइयां हैं, जो विभिन्न प्रकार की धातुकर्मीय मशीनरी के निर्माण में लगी हैं। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उत्पादन क्रमश: 290.89 करोड़ रुपए और 200.08 करोड़ रुपए था। इन उपकरणों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में वर्तमान उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। किन्तु लौह और अलौह धातु क्षेत्र में प्लांटों और औजारों के बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल है, जिसके लिए घरेलू विनिर्माताओं को आयातित जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। चूँकि, लोह और अलौह धातु को प्रोसेस करने का संबंध उपकरण के डिजाइन के साथ होता है, अत: प्रोसेस की जानकारी रखने वालों, डिजाइनों और औजार निर्माताओं के बीच अंतर-सम्पर्क आवश्यक है। देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक ब्लास्ट फर्नेसिस सिंटर प्लांटों, कोक ओवन्स, स्टील मेल्टिंग शॉप उपकरण, सतत कास्टिंग उपकरण, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन जैसे अधिकतर उपकरण उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। धातुकर्मीय मशीनरी उद्योग का निर्यात और आयात 2001-2002 में क्रमश: 191.80 करोड़ और 126.60 करोड़ रुपए मूल्य का रहा।

खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपकरणों में लांगवाल माइनिंग उपकरण, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एल एच डी), हौलेज विंडर, वेंटिलिएशन फैन, लोड हौलडम्पर (एल एच डी) कोल-कटर, कन्वेयर्स, बेटरी लोको, पम्पस, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं। वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तहत संगठित क्षेत्र में 32 ऐसे विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन-उपकरणों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपकरणों का विनिर्माण करती हैं। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए उत्पादन क्रमश: 149.52 करोड़ रुपए और 238.86 करोड़ रुपए था। खनन उद्योग को खनन उपकरणों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी अधिकतर आपूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती हैं। अत्याधुनिक उपकरणों के मामले में महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों का आयात किया जाता है। 2001-2002 के दौरान इस क्षेत्र का निर्यात और आयात क्रमश: 11 लाख रुपए और 28.93 करोड़ रुपए मूल्य का रहा।

डेयरी मशीनरी उद्योग

वर्तमान में देशी निर्माताओं द्वारा बनाए जा रहे उपकरणों में स्टेनलेस स्टील डेयरी उपकरण, इवैपरेटर, मिल्क रेफ्रिजेरेटर और भंडारण टैंक, मिल्क ओर क्रीम डेओडोजर्स, सेंट्रीफ्यूजिज, क्लेरिफाइर्स, ऐजिटेटर्स, होमजेनाइजर्स, स्प्रे डायर्स और हीट ऐक्सचेंज़र (ट्यूबलर और प्लेट टाइप) आदि शामिल हैं। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 16 इकाइयां ऐसी हैं, जो डेयरी मशीनरी और उपकरणों के

विनिर्माण में लगी हैं। हाल के वर्षों में मैसर्स एन डी डी बी द्वारा अनेक डेयरी प्लांट चालू किए गए, जिनके लिए अधिकतर उपकरण देशी विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए। इन मिल्क पाउडर प्लांटों के लिए स्प्रे डायर्स, प्लेट टाइप, हीट ऐक्सचेंज़र और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती हैं, क्योंकि किसी भी माइक्रोसरेविस के बचे रहने से बैक्टीरिया को सांस लेने या प्रजनन का आधार मिल सकता है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उत्पादन क्रमशः 14.8 करोड़ रुपए और 14.53 करोड़ रुपए था। डेयरी उद्योग के लिए लघु उद्योग क्षेत्र भी विनिर्मित उपकरणों के देशी उत्पादन में योगदान कर रहा है। किन्तु सेल्फ क्लिनिंग क्रीम, सेपरेटर, असेप्टिक, प्रोसेसिंग सिस्टम आदि प्रहस्तन उपकरणों के मामले में प्रौद्योगिकी संबंधी अन्तराल बना हुआ है। दही (योगहर्ट) और परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए आवश्यक प्लांट उपकरणों से सम्बद्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में, तेज गति से आइसक्रीम बनाने की मशीनों का निर्माण भी भारत में नही किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान डेयरी और मिक्सिंग उपकरणों का अनुमानित निर्यात और आयात क्रमशः 535 लाख रुपए और 278 लाख रुपए मूल्य का रहा।

मशीन टूल्स उद्योग

मशीन टूल उद्योग औद्योगिक इंजीनियरी क्षेत्र की रीढ़ है। विगत चार दशक के दौरान भारत में मशीन टूल उद्योग ने अपना एक मजबूत आधार स्थापित कर लिया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 125 मशीन टूल विनिर्माता और लघु सहायक उद्योग क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां हैं।

भारतीय मशीन टूल्स गुणवत्ता/परिशुद्धता और विश्वसनीयता के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। अधिकतर प्रमुख विनिर्माताओं ने सीएनसी मशीन टूल्स पहले ही विकसित कर लिए हैं। आधुनिकतम मशीन टूल्स के इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने के लिए अनेक सहयोग समझौतों को अनुमोदित किया गया है और उद्योग अब परंपरागत एवं एन सी/सीएनसी उच्च प्रौद्योगिकी वाले मशीन टूल्स का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर अधिक उपयुक्त डिजाइन वाले मशीन टूल्स के लिए अग्रणीय अनुसंधान कर रहा है। इस क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और आयात की अनुमति दी गई है। विशेष प्रयोजन मशीनों और सीएनसी मशीन टूल्स की कुछ श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकी में अन्तर है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मशीन टूल्स विनिर्माता संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उत्पादन, आयात और निर्यात इस प्रकार रहा:

(करोड़ रुपए)

	2000-2001	2001-2002
उत्पादन	585.00	516.00
आयात	341.00	311.00
निर्यात	30.00	48.00

आटोमोटिव उद्योग

आटोमोटिव उद्योग

पर्यवलोकन

देश के त्वरित आर्थिक और औद्योगिक विकास में मजबूत परिवहन प्रणाली की अहम भूमिका है। अच्छी तरह विकसित भारतीय आटोमोटिव उद्योग सवारी कार, हल्के और मध्यम तथा भारी व्यावसायिक वाहन, जैसे जीप, स्कूटर, मोटर-साइकिल, मोपेड, श्री-व्हीलर, ट्रेक्टर आदि जैसे बहुउपयोगी वाहनों का उत्पादन कर सुचारू रूप से इस प्रेरक भूमिका को अदा कर रहा है। आटोमोबाईल उद्योग अर्थव्यवस्था में सर्वत्र एक महत्वपूर्ण वाहक रहा है। यद्यपि, भारत में आटोमोबाईल उद्योग लगभग छह दशक पुराना है, फिर भी 1982 तक मोटर कार के क्षेत्र में केवल 3 विनिर्माता-मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स, मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाईल्स और मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर्स है। कम मात्रा होने के कारण यह लगातार पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाता रहा और विश्व उद्योग की तुलना से बाहर था। वर्ष 1982 में मारूति उद्योग लिमिटेड को तत्कालीन माडलों की भारी मात्रा में उत्पादन की स्थापना करने के लिए जापान की सुजुकी के साथ सहयोग से सरकार द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1993 में लाइसेंस हटाए जाने के बाद 18 नए उद्यम स्थापित किए गए, जिनमें से 17 कार निर्माता हैं।

आटोमोटिव तथा वाहनों के कल पुर्जों का निर्माण करने वाले आटोमोटिव उद्योग ने 1993 में लाइसेंस प्रणाली हटा लेने तथा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के लिए रास्ता खोले जाने के बाद से काफी प्रगति की है। 31.3.2000 तक इस उद्योग में पूंजी निवेश 50,000 करोड़ का है। वर्ष 2000-2001 में आटोमोटिव उद्योग का कुल कारोबार 63025 करोड़ रुपए से अधिक का था। आटो पुर्जा उद्योग के कारोबार को शामिल कर आटोमोटिव उद्योग का कारोबार लगभग 81600 करोड़ रुपए से अधिक का था। यह उद्योग 4.5 लाख लोगों के लिए परोक्ष रूप में रोजगार पैदा करता है तथा 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में इस उद्योग का योगदान 1992-93 के 2.77 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 4.00 प्रतिशत हो गया।

स्थापित क्षमता

वर्ष 1993-94 से क्षमता स्थापना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-2002 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग की स्थापित क्षमता नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	खण्ड	स्थापित क्षमता (संख्या)
1.	वाणिज्यिक वाहन	15,00,000
2.	दुपहिया और तिपहिया	64,00,000
	कुल जोड़	79,00,000

वर्ष 2001-2002 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग का कार्य निष्पादन

संपूर्ण आटोमोबाइल उद्योग ने 2001-2002 में 13.19% विकास दर प्राप्त की है। तथापि, चालू वर्ष अर्थात 2002-2003 में अप्रैल-नवम्बर तक की अवधि में गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि अर्थात 2001-02 (अप्रैल-नवम्बर) की तुलना में भारतीय आटोमोबाइल उद्योग ने 22.14% की वृद्धि दर्शायी है।

वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा गत वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ नीचे दिया गया है:-

(संख्या में)

क्रम सं.	उद्योग का नाम	2001-2002 (पूरा वर्ष)		2002-2003 (अप्रैल-नवम्बर)	
		इकाई की संख्या	उत्पादन	इकाई की संख्या	उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1.	वाणिज्यिक वाहन	9	146197	9	124758
2.	कार	12	564126	12	350152
3.	बहुउपयोगी वाहन	5	123748	5	100064
4.	दुपहिया	12	4323644	12	3443331
5.	तिपहिया	4	212753	4	176646
	जोड़	**42**	**5370468**	**42**	**4194951**

आटोमोबाइल उद्योग भी देश के निर्यात प्रयास में योगदान कर रहा है। 2001-2002 तथा 2002-2003 में (नवम्बर तक) निर्यात ब्योरा निम्नलिखित है:-

(मात्रा संख्या में)

क्रम सं.	वाहनों की किश्म	2001-2002	2001-2002 (अप्रैल-नवम्बर)	2002-2003 (अप्रैल-नवम्बर)
1.	मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन	4656	2438	2885
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	6770	4282	3643
3.	कारें	50108	29969	42876
4.	जीपें	3548	2307	1079
5.	दुपहिया वाहन	103381	64590	111330
6.	तिपहिया वाहन	13425	8388	28178
	जोड़	**184188**	**111974**	**189991**

सरकार ने प्रदूषण और सुरक्षा जांच आरंभ की तथा इस संबंध में 1992 में उत्सर्जन और सुरक्षा मानक की अधिसूचना जारी की और अप्रैल, 1996 में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत इन्हें और कठोर बनाया गया।

यूरो-I उत्सर्जन मानदंड को देश भर में पहले ही लागू किया जा चुका है और भारत अप्रैल, 2005 तक यूरो-II मानदंड को देश भर में लागू करने वाला है।

उक्त तारीख से 7 महानगरों में यूरो-III मानदंड लागू कर दिया जाएगा। नए उत्सर्जन मानदंडों की उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय आटोमोबाईल उद्योग पहले ही नए निवेश लगाकर नई प्रौद्योकियां अपना चुका है। घरेलू तौर पर उत्पादित और आयातित उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक उच्चतर सुरक्षित उत्सर्जन मानव के प्रणाली के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। देश में विद्यमान परीक्षण ढांचा सीमित है और आटोमोबाईल उद्योग की भावी तथा उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं। इसलिए, देश में परीक्षण ढांचे की स्थापना और उसका उन्नयन करने की आवश्यकता है। सरकार ने उद्योग के साथ निकट सहयोग और समूल्य से वर्तमान परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन और देश में नए परीक्षण ढांचे की सहायता करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ऑटोमोबाईल कलपुर्जा उद्योग

पर्यवलोकन

ऑटोमोबाईल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रवाही संयोजन अत्यंत विविध और गतिशील ऑटोमोबाईल कलपुर्जा क्षेत्र है, जोकि भारत में 20,000 करोड़ रुपए के कारोबार वाला क्षेत्र है तथा यह वाहन निर्माण के लिए सभी महत्वपूर्ण कलपुर्जों का उत्पादन करता है।

1980 के दशक के दौरान अपनाई गई योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया ने भारतीय ऑटोमोबाईल कलपुर्जा क्षेत्र के विकास में भारी सहयोग दिया है। 1980 के दशक में अपनाई गई चरणबद्ध विनिर्माण नीति (पीएमपी) ने कलपुर्जा उद्योग को नई प्रौद्योगिकियां, नए उत्पाद शामिल करने और उनके प्रचालनों में उच्च स्तर की गुणवत्ता को शामिल करने में सहायता की है, जिससे कलपुर्जा आधार के शीघ्र और कारगर स्थानीयकरण में सहायता मिली है। इस प्रकार, भारतीय ऑटोमोबाईल कलपुर्जा उद्योग ने विगत में देश के ऑटोमोबाईल उद्योग के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

आज भारतीय ऑटोमोबाईल कलपुर्जा क्षेत्र में 411 महत्वपूर्ण भागीदार हैं, जोकि इस क्षेत्र के उत्पादन में 85 प्रतिशत सहयोग

करते हैं। ऑटोमोबाईल कलपुर्जा क्षेत्र से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

	2001-2002
निवेश	10,700 करोड़ रुपए
उत्पादन	20,000 करोड़ रुपए
निर्यात	2,775 करोड़ रुपए
रोजगार	2,50,000 व्यक्ति

वर्ष 2001-2002 के दौरान आटोमोबाइल कलपुर्जा उद्योग का कार्यनिष्पादन

गत वर्ष में भारतीय ऑटोमोबाईल कलपुर्जा उद्योग ने अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति की है। जबकि अर्थव्यवस्था मंदी चल रही थी और जीडीपी में मात्र 4 प्रतिशत वृद्धि हुई, तब भी ऑटोमोबाईल कलपुर्जा के उत्पादन में वर्ष 2001-2002 में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में उत्पादन 20,000 करोड़ रुपए का था, जबकि इसकी तुलना में 2000-01 के दौरान यह 17,246 करोड़ रुपए था।

निर्यात क्षेत्र में ऑटोमोबाईल कल पुर्जों के उद्योग ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की 2001-2002 में आटो पुर्जों का कुल निर्यात 2775 करोड़ रुपए का था, जबकि गत वर्ष में यह 2706 करोड़ रुपए का रहा था।

कृषि संबंधी मशीनरी

कृषि मशीनों में मुख्यत: कृषि संबंधी ट्रैक्टर, पावर टिल्लर्स, कम्बाइन हारवेस्टर्स तथा अन्य मशीनें और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिल्लर्स, कम्बाइन हारवेस्टर्स तथा अन्य मशीनों के नाममात्र उत्पादन के कारण इस क्षेत्र में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है।

कृषि ट्रैक्टर

इस समय संगठित क्षेत्र की 14 इकाइयां कम अश्व शक्ति के 16-20 अश्व शक्ति से 50 उच्च अश्व शक्ति के विभिन्न कृषि ट्रैक्टरों का विनिर्माण कर रही हैं। इस उद्योग की शुरूआत 1961 में कुल 880 नग उत्पादन के साथ हुई थी। ट्रैक्टरों के उत्पादन में 1980 के दशक में अंतिम वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ है और 2000-2001 में यह 2,34,575 तक पहुँच गया है। विगत कुछ वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों के हुए उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	संख्या
1998-99	2,53,850
1999-2000	2,66,385
2000-2001	2,34,575

यद्यपि, ट्रैक्टर उद्योग ने उत्पादन यूएसए, यूके, रूस, जर्मनी, पोलैण्ड चेकोस्लोवाकिया में प्रसिद्ध विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी आयात करके शुरू किया था। कुछ ट्रैक्टर विनिर्माताओं ने उच्च अश्व शक्ति श्रेणी के ट्रैक्टरों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयातित कल-पुर्जों के साथ 75 अश्व शक्ति के उच्च अश्व शक्ति ट्रैक्टरों का उत्पादन आरम्भ किया है।

ट्रैक्टरों के कुल उत्पादन में 60 प्रतिशत हिस्सा 31-40 एच पी ट्रैक्टरों का, 23 प्रतिशत हिस्सा 41 एच पी और अधिक एच पी ट्रैक्टरों का, तथा 17 प्रतिशत हिस्सा 30 एच पी से छोटे ट्रैक्टरों का है। परंपरागत रूप से हरियाणा, पंजाब, और उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर बाजार के प्रमुख प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में ट्रैक्टर बाजार और तेजी से विकसित हो रहे हैं।

मिट्टी हटाने तथा भवन निर्माण की मशीनें

मिट्टी हटाने के उपकरण तथा निर्माण मशीनी उद्योग हमारे देश में आर्थिक विकास में अहम् भूमिका निभाता रहा है। यह उद्योग की प्रमुख विकासात्मक तथा संरचनात्मक योजनाओं जैसे कोयला तथा खनिज उत्खनन, सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं, बंदरगाह, इस्पात, उर्वरक आदि के निकट रूप से संबंध हैं। ऐसी मशीनों के निर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले उपलब्ध नहीं थी। अत: यह आवश्यकता हो गया था कि कोमत्शु केटरपिलर, पोक्लेन, ड्रेसर, डेमग और हिटैची जैसे

अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात विनिर्माताओं के उसके विकास के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की अनुमति दी जाए। आजकल विनिर्माण किए जा रहे मिट्टी हटाने के उपकरणों में 10 घन मीटर तक क्षमता वाले शावेल्स, 770 अश्व शक्ति तक के बुल्डोजर, 120 अश्व शक्ति तक के डम्पर, 8.5 घनमीटर क्षमता के एक्सावेटर, 280 अश्व शक्ति तक के स्क्रेपर तथा मोटर ग्रेडर्स तथा वाकिंग ड्रेगलाइन, सचल क्रेन आदि शामिल हैं। भवन निर्माण उपकरण विशेषकर सड़क निर्माण उपकरण जैसे ग्रेडर्स, लोडर्स, एक्सकवेटर, वाइबेटर, कंपैक्टर, हॉटमिक्स प्लांट आदि का देश में ही निर्माण किया जा रहा है। ये मशीनें, सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं, कोयला तथा लौह अयस्क खनन, सीमेंट के लिए चूना पत्थर की खुदाई, भूमि पर बड़े ट्रैक बनाने, सड़क बनाने, नहर बनाने, औद्योगिक स्थल तैयार करने तथा देश की विकास गतिविधि के सभी पहलुओं में तीव्रता से विकास के लिए सहायता करती हैं। इन मशीनों ने श्रम की निर्भरता को कम किया है तथा निर्माण कार्य में आटोमेशन प्रदान किया है।

मिट्टी हटाने और निर्माण की मशीनरी का देश में उत्पादन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। आज कुल मिलाकर इन मदों के संबंध में देश पूर्णत: आत्मनिर्भर है। वास्तव में, पिछले दशक के दौरान उद्योग ने बहुत प्रगति की है। अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण उद्योग में उपलब्ध कुल क्षमता लगभग 6000 नग हैं। भारत में अनेक मध्यम आकार की इकाइयों के अलावा संगठित क्षेत्र में 60 से अधिक उपकरण विनिर्माता हैं। इस उद्योग में प्रत्येक उत्पाद खंड में कुछ बड़े विनिर्माताओं का दबदबा है। बीईएमएल और केटर फिल्लर डम्पर और डोजर्स में जब कि एल एंड टी कोमात्सु और टेलकॉम खुदाई उपकरणों में और एस्कार्टस जेसीबी बेकहो लोडर्स में अग्रणी हैं। सरकार द्वारा ड्डाधारभूत ढांचे के विकास पर बल और प्राथमिकता दिए जाने से उद्योग के इस समूह के निकट भविष्य में विकसित होने की आशा है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्पादित अर्थ–मूविंग और निर्माण उपकरणों की संख्या उनके निर्यात सहित नीचे दर्शायी गई है:

वर्ष	**उत्पादन (संख्या में)**	**निर्यात (मिलियन रुपए)**
1999–2000	6717	120
2000–2001	7605	40
2001–2002	6853	210

प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास

किसी भी उद्यम के लिए बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने और बने रहने के लिए सतत, जागरूक और तीव्र बल देते हुए अनुसंधान एवं विकास प्रयास करना एक अनिवार्य शर्त है। उद्योग क्षेत्र में विनियंत्रण लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हमारे दरवाजे पर पहुंच गई है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी का विश्व मानकों के अनुरूप उन्नयन करना आवश्यक हो गया है। प्रयोक्ता क्षेत्र की मांग प्रौद्योगिकियों के चयन और उत्पादों की शुरूआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वास्तविकताओं को देखते हुए, भारतीय उद्योग को, जोकि पिछले चार दशक से सुरक्षा प्राप्त कर रहा था, स्वयं को तैयार करना होगा और तत्काल कार्रवाई करनी होगी। अनुसंधान एवं विकास पर बल देने के महत्व को समझते हुए सरकार ने कुछ उत्प्रेरक कार्रवाई बिंदुओं पर विचार किया है। इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों ने भी तकनीकी और व्यावसायिक गठबंधनों तथा शुद्धत: अनुसंधान एवं विकास निविष्टियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन क्षेत्रों में देश को विशिष्ट लाभ प्राप्त हैं, वहां पर देश के लिए ब्राडं छवि विकसित करने के लिए उन क्षेत्रों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में विभाग द्वारा आरंभ किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसंधान एवं विकास संबंधी एक जानकारी प्रबंध समूह जुलाई, 2002 में गठित किया गया था, ताकि विश्व में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और उनकी भारतीय उद्योग में प्रासंगिकता का पता लगाया जा सके। इस समिति के विचारार्थ विषयों में भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास की प्रगति की समीक्षा करना आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की सिफारिश करना जिन क्षेत्रों में देश लाभ की स्थिति में है, उन्हें मजबूत बनाना तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का वितपोषण करना शामिल है।

2. यह माना गया है कि उदारीकृत परिवेश में देश को कुछ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अग्रणी बनना होगा, जहाँ पर भारत को संवर्धन के लिए निर्धारित कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की उन्नति के लिए तुलनात्मक लाभप्रद सुविधाएं प्राप्त है। इस दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों का नीचे उल्लेख किया गया है।

(i) एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना

आईजीसीसी संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र है, जिसमें कोयले (अथवा रिफायनरी अवशिष्ट जैसे कोर्ब अन्य कार्बनिक ईंधन यथा; पैट कोक, विसब्रेकर तारकोल) के गैसीकरण द्वारा गैस टरबाइन के लिए ईंधन गैस पैदा की जाती है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के चयन और उचित डिजाइन वाले गैस टरबाइन के साथ इसका दक्षता समन्वय आईजीसीसी संयंत्र की उच्चतर समग्र दक्षता प्राप्त करने में सर्वोच्य महत्व रखता है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के तीन मूलभूत व्यापक प्रकार हैं; यथा:-

(क) सचल सतह

(ख) आरूढ़ सतह, और

(ग) द्रवीकृत सतह।

भेल ने अधिक राख अंश वाले स्थानीय कोयले के लिए उपयुक्त एक प्रौद्योगिकी विकसित करने में पहले ही कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। इसलिए, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए 100 मेगावाट क्षमता के प्रोटोटाइप का विकास करने के वास्ते विद्युत क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों यथा विद्युत विभाग, सीईए, एनटीपीसी, भेल, भारी उद्योग विभाग के सक्रिय सहयोग के साथ एक परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना के परिणामस्वरूप "अधिक राख" वाले भारतीय कोयले का बेहतर उपयोग होगा और विद्युत उत्पादन की दक्षता में सुधार होगा तथा प्रदूषण कम होगा।

(ii) आटो क्षेत्र के लिए परीक्षण सुविधाएं

भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और उसके परिणामस्वरूप माल और यात्रियों की आवाजाही की आवश्यकताओं के कारण हाल के वर्षों में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। विश्व

की अनेक बड़ी आटामोबाईल कंम्पनियों ने भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं, जिससे स्थापित क्षमता बढ़कर 79 लाख वाहन प्रतिवर्ष हो गई है और इसमे लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश लगा हुआ है। इसके साथ-साथ उत्सर्जन और सुरक्षा संबंधी सांविधिक विनियमों के लागू होने से वाहनों का स्वतंत्र एवं व्यापक परीक्षण आवश्यक हो गया है तथा उनके प्रमुख कल-पुर्जों तथा छोटे कल-पुर्जों का देश में विनिर्माण और आयात किया जा रहा है। छोटी कारों के विनिर्माता के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के तौर पर स्थापित करने की घोषित नीति के अनुरूप,अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुरूपता लाने के लिए तथा आटो क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

3. सरकारी उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को ब्योरा नीचे दिया गया है:-

भेल

आंतरिक अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकासों के माध्यम से उत्पादों और प्रणालियों का वाणिज्यकरण करके गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान 613.13 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया गया। अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, नए उत्पाद/प्रणाली विकास और विश्वसनीयता/गुणवत्ता/लागत के संदर्भ में उत्पाद सुधार तथा आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान देते हुए 87.14 करोड़ रुपए (कुल कारोबार का 1.2%) की राशि व्यय की गई। प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने पर ये प्रयास हल्के जान पड़ते हों, फिर भी परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन में प्राप्त कुछ उपलब्धियां तथा कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:-

— भेल द्वारा देशीय तौर पर विकसित भारत के सर्वाधिक क्षमता वाले वातावरणीय द्रवीकृत सतह प्राज्वलन (एएफबीसी) बायलरों (2×165 टन/घंटा) को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायगढ़ में सफलतापूर्वक चालू किया गया है। कोयला, धोवनशाला छीजन और चारकोल जैसे विभिन्न ईंधनों को प्रज्वलित करने में सक्षम इन बायलरों के विकास से भेल बहु-ईंधन विकल्पों के साथ भारी क्षमता वाले एएफबीसी बायलरों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा।

— देश में पहली बार, भेल ने जिन स्थानों पर ऊपरी लाइन बिछाना महंगा या अव्यावहारिक होता है, वहाँ पर भारी मात्रा में विद्युत के पारेषण के लिए 420 केवी गैस इंसुलेटिड बस डक्ट का विकास किया है। इन बस डक्टों का मुख्य प्रयोग भूमिगत जल विद्युत केन्द्रों से भूतल पर स्थित उपकेन्द्रों में विद्युत परिषण के लिए किया जाता है।

— नियंत्रण और विद्युत केबल को हटाकर स्वत: भंडारण पुन: प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस)का एक उन्नत डिजायन विकसित किया गया है। स्टैकर क्रेन और नियंत्रण क्यूबिकल के बीच नियंत्रण संकेतों को अब रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) के माध्यम से अदला-बदला जा सकता है।

इसरो के लिए उपग्रह प्रयोग हेतु भेल, बंगलौर में एकत्रित प्रथम स्पेस ग्रेड सोलर पेनल

वर्ष 2002-2003 के अंत तक पूरी की जाने वाली प्रमुख अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है:-

- सीएफबीसी बायलरों के लिए 2002 एनएम/3 घंटे का विकास और क्षेत्र में परीक्षण।
- 5 एमवीए सुपरकंडक्टिग जेनरेटर का विकास।
- विशेष किस्म के 3-डी इम्पेलर का प्रयोगात्मक निष्पादन मूल्यांकन।

- डब्ल्यूसीएएम 3 एसी/डीसी रेल इंजिनों के लिए मुख्य स्टार्टर प्रतिरोधकों का डिजायन, विकास और परीक्षण।
- स्टेटिक टैप चेंजर के साथ फेन उठाने वाले ट्रांसफार्मर का विकास।
- 145 केवी जीआईएस के विद्युत माध्यम क्षेत्रीय परीक्षणों की शुरूआत।
- 500 मी. हैड के लिए उपयुक्त फ्रांसिस हाइड्रो टरबाइन मॉडल का विकास।
- कुट्टियाड़ी जल-विद्युत संयंत्र के लिए चार जेट पेल्टॉन टरबाइन मॉडल का विकास।
- उन्नत डिजायन के एफआर 9 ई ठोस टरबाइन आवृत खंडों के विनिर्माण की स्थापना।
- उन्नत हवादार प्रणाली के साथ फ्रेम 6 गैस टरबाइन के लिए 60 हार्टज जेनरेटर के डिजायन का विकास।
- गाद वाले सलाल जल विद्युत केन्द्र के लिए नई संसोधित शाफ्ट सील का विकास।
- पैकेज टाइप बायलर में बनाए भट्टी गैस ज्वलन की स्थापना।
- बायलरों में प्रयोग हेतु गर्म प्रारंभिक वायु के लिए एरोफॉयल ब्लेड वाले पंखे का विकास।

भेल द्वारा आपूर्ति किया गया इटारसी स्विचिंग स्टेशन में 400 केवी., 50 एमवीएआर नियंत्रित शंट रिएक्टर

बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. (बीएससीएल)

कंपनी द्वारा चालू वर्ष 2002-2003 के दौरान आरंभ किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

(i) कंपनी के सेलम कारखाने में मेकॉन के सहयोग से मैगनिशियम एल्यूमिना और मैगनिशियम क्रोम स्पाइनल के विनिर्माण की एक परियोजना पर कार्य चल रहा है। पूरा होने पर सेलम कारखाना उच्च किस्म की ईंटे तैयार करने में सक्षम होगा, जिनका सीमेंट/कांच उद्योग में प्रयोग किया जाएगा।

(ii) बर्नपुर कारखाने ने विशेष प्रयोजन वैगन (बीटीएपी) में अंत) निर्मित वायु फ्लूडाइजिंग प्रणाली की तकनीक प्राप्त कर ली है और बॉटम डिस्चार्जड वैगनों के लिए इलैक्ट्रो-न्यूमेटीकली प्रचालित डीओएम का पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस विकास से लागत में कमी आई है और निर्यात प्रतिस्थापन हुआ है।

(iii) इलैक्ट्रिकल विद्युत उत्पादन और शहरी तथा आर्गेनिक ठोस कचरे से बायो-गैस/जैव-उर्वरक का उत्पादन

(iv) मैग्नेसाइट से सिलिका अलग करने के लिए उच्च शक्ति के चुम्बक।

(v) पटसन की रद्दी और एमएसडब्ल्यू कंपोसिट से माइक्रोवेव प्रेरित बायोमिथेनेशन।

(vi) आनुवंशिकीय परिवर्तित सूक्ष्म अवयव प्रयोग करते हुए जूट मिल्स और जूट कालोनी से अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन।

(vii) जैव-अवक्रमणीय शहरी ठोस कचरे को जैव-ऊर्जा (बिजली, बायो-गैस और उप-उत्पाद के रूप में एनपीके आर्गेनिक खाद) में परिवर्तित करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां कैप्टिव संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

(viii) जैव-प्रौद्योगिकी में वायुजीवी फफूंद विकास प्रणाली तकनीकों का प्रयोग करते हुए ओपन डम्प लीन्पिंग के माध्यम से मैग्नेसाइट का सुधार (अशुद्ध रूप में सिलिका को अलग करना। सेलम कारखाने में प्रयोगात्मक परीक्षण पहले ही आरंभ हो चुके हैं।

इंस्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा (आईएलके)

प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रक्रिया विशेषकर डीडीसी श्रृंखला, नियंत्रण वाल्व श्रृंखला, यूपीएस श्रृंखला और अन्य उत्पादों के लिए तत्परता से अपनाई जा रही है। दूरसंचार क्षेत्र में सी-डॉट प्रौद्योगिकी को अन्यंत उन्नत बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक स्विचों के विनिर्माण के

लिए पूरी तरह समाहित कर ली गई है। कंपनी ने आईएसडीएन विशेषता और रिमोट लाइन कंसंट्रेटर (आरएलसी) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीयां प्राप्त करने के लिए आगे कार्रवाई की है। डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए भी कार्रवाई की गई हैं। वितरित अंकीय नियंत्रण प्रणलियों (डीडीसीएस) की अन्य प्रमुख उत्पाद श्रृंखलाओं के लिए कंपनी इस क्षेत्र में अन्य प्रसिद्ध भागीदारों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पता लगा रही है। इसी प्रकार, कंपनी यूपीएस श्रृंखला के लिए प्रमुख विनिर्माताओं का पता लगा रही है, ताकि बड़े आकार में लगातार वोल्टता आकृति (सीवीसीएफ) यूपीएस और अंशीय केवीए श्रेणी सहित छोटे यूपीएस और दूरससंचार प्रयोगों के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई (एसएमपीएस) के लिए आईजीबीटी प्रौद्योगिकी की शुरूआत की जा सके।

एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी और सहायक कंपनियां)

कंपनी ने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न उत्पादों के वास्ते अपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं स्थापित की हैं। अनुसंधान एवं विकास का जोर उत्पाद प्रौद्योगिकी में लगातार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और विशिष्टताओं के सौंदर्य तथा मूल्य के संबंध में प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने पर रहता है।

उत्पाद प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, विश्वसनीयता के उन्नयन और विशेषकर उपभोक्ता जरूरतों के संदर्भ में मूल्य प्रतिस्पर्धा के लिए इसकी प्रत्येक सहायक कंपनी में अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाते हैं। अतिरिक्त विशेषताओं, डिजायन इष्टतमीकरण के साथ विद्यमान उत्पादों का उन्नयन और सौंदर्य में सुधार विशेष बल दिए जाने वाले क्षेत्र हैं। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप नए उत्पाद सामने आए हैं और ट्रैक्टरों सहित विद्यमान उत्पादों का उन्नयन भी किया गया है।

मशीन टूल सहायक कंपनी ने वीएसएससी, त्रिवेन्द्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी फाइव एक्सिस गैण्ट्री पावर मिल का डिजायन और विनिर्माण किया। इस मशीन का विकास करने पर एचएमटी को इसके अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए डीएसआईआर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

पहिया और एक्सिल संयंत्र (डब्ल्यूएपी) के लिए मशील टूल सहायक कंपनी ने पूर्णतः स्वचालित लदान/उतराई प्रणाली के

एमएमटी द्वारा डिजायन एवं विनिर्मित किया गया उच्च प्रौद्योगिकी फाइव एक्सिस गैंट्री पावर मिल

साथ एक्सिल मशीन के लिए उच्च शक्ति की 16 एक्सिस सीएनसी की मशीन का डिजायन और विनिर्माण किया।

एण्ड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का मुख्य बल मौजूदा उत्पादों का सतत उन्नयन करने पर रहा है, ताकि वे घरेलू बाजार का मुकाबला कर सकें और निर्यात बाजार में अवसर प्राप्त कर सकें। इस कार्य में नए उत्पादों का विकास, उत्पाद विस्तार और प्रोटोटाइप विकास एवं वाणिज्यकरण द्वारा आगे आने वाली उच्चतर ऋंखलाओं के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र को पुनः मान्यता दिलाना शामिल हैं। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास ढांचे को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने मान्यता दी हुई है। कंपनी की विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:–

(क) नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए स्विचगियर इकाई ने 12 केवी, 400 केए इंडोर सर्किट ब्रेकर पेनल, 6.6 केवी, 400ए वैक्यूम कंट्राक्टर पैनल, 33 केवी 1600ए पोर्सेलिन क्लैड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का विकास किया है।

(ख) ब्रेटफोर्ड इकाई में शुष्क किस्म के 315 केवीए 6 केवी और 11 केवी/33 केवी शुष्क किस्म के ट्रांसफार्मर का विकास किया है।

(ग) तोगामी इकाई ने स्वयं निम्नलिखित का विकास किया है:

(i) बी 21 VI के साथ 12 केवी लेन्च टाइप सेक्शनलाइजर स्विच

(ii) सीजीएल VI के साथ 12 केवी 400 ए 20 के ए वैक्यूम कैप स्विच और 100 ए तथा 150 ए एकल खंभा डी सी मोल्डिड केस सर्किट ब्रेकर्स।

इसके अलावा, बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंट्रोल पैनल के साथ ऑयल फील्ड ऑटो रिक्लोजर की विकास प्रक्रिया प्रगति पर है।

(घ) ट्रांसफार्मर एवं स्विचगियर इकाई ने एसएफ 6 के साथ रिंग मेन यूनिट और 12 केवी 630 ए, 25 केए 95 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों का भी विकास किया है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

कंपनी द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान आरंभ किए गए प्रौद्योगिक उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(क) डाइजास्टार्टर के स्थान पर स्टार्टर मोटर और आल्टरनेटर के प्रावधान के लिए जल-शीतलन इंजिन के साथ विक्रम 750 डी।

(ख) सीएनजी प्रचालित विक्रम 410 जी का स्वत: चालू संस्करण विकसित

(ग) एलपीजी प्रचालित विक्रम 600 जी विकास परीक्षण के अधीन है।

(घ) इलैक्ट्रिक तिपहिया वाहन का 3 सीट वाला आटोरिक्शा संस्करण विकसित किया जा रहा है।

(ङ) जीवन-काल बढ़ाने के लिए विक्रम 450 डी के चेसिस संशोधित।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच ई सी)

कंपनी द्वारा आरंभ किए गए कुछ अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र के साईक्लोट्रान चुम्बक, रैमिंग गन, 8 टन गर्थ गियर, पोत निर्माण के लिए बल्ब बार और अन्य के विकास से संबंधित हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)

कंपनी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने जेलीपूरित केबलों और ऑप्टीकल फाइबर केबल के लिए नई और सस्ती मूलभूत कच्ची सामग्रियों के मानकीकरण के लिए अपने प्रयास जारी रखें। इसने ऊपरी आवरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अधिक व्यास वाला ऑप्टीकल प्रिफार्म विकसित किया है।

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन (एच पी सी)

कंपनी द्वार अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयास निम्नलिखित हैं:

(i) पारिस्थितकी अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाकर लुगदी और विच्छेदन प्रक्रिया में सुधार।

(ii) ऊर्जा खपत में कमी करना।

(iii) प्रदूषण भार में कमी लाना तथा निस्सारी का उपचार।

प्रौद्योगिकी समाहित करने, अपनाने और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- एनपीएम और सीपीएम के लुगदी मिल में डायनोमिक क्लोरीन मिक्सर की स्थापना।
- एनपीएम में जेसप एंड उटमल मशीन के लिए डिस्क फिल्टर सेवाल की स्थापना।
- एनपीएम में फालिंग फिल्म फिनीशन की स्थाना।
- एन पी एम में उटमल मशीन के लिए डूयोफ्लो की स्थापना।
- न्यूमेटिक से इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में चरणबद्ध परिवर्तन।
- एनपीएम और सीपीएम में प्रयोगशाला उपस्कर की स्थपना।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ:

- क्लोरीन की खपत में कमी।
- ताजा जल की खपत में कमी और फाइबर तथा फिलर का परिवर्तन।
- भाप की बचत और अधिक ठोस सांद्रण में सुधार।

4. नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

विगत में, नयी टेक्नोलाजी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच संस्थान स्थापित किये गये हैं। ये हैं: द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान; प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, सेंटर

फार इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेशन, भोपाल; सेरेमिक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर और वैल्डिंग अनुसंधान संस्थान।

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफ सी आर आई) को प्रवाह नियंत्रण/परिशुद्धता के साथ मापन में संदर्भ/मानकीकरण का ढांचा विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जोकि द्रव प्रवाह के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक इंजीनियरी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है। यह सभी प्रकार के प्रवाह उत्पादों के लिए परीक्षण और अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसने अनेक संगठनों की संदर्भ/प्रमुख उपकरणों का राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंशांकन और आईएसओ–9000 पद्धति अपेक्षाओं में निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान कर आईएसओ–9000 प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता की है। भारत में पेट्रोलियम कंपनियों को परीक्षण कराने के लिए 20 बार एचपी तक वायु प्रवाह अंशांकन और परीक्षण सुविधा पहले की स्थापित कर चुका है।

एफसीआरआई स्थित 20 बार क्लोज लूप एअर परीक्षण सुविधा में नीदरलैण्ड्स से आए हुए विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मुख्य एजेंसी की भूमिका सौंप कर दी है। संस्थान की परियोजना का उद्देश्य आर्थिक विकास के अवांछित दुष्परिणामों से बचने के लिए हवा, पानी, आवास और ठोस अपशिष्ट से संबंधित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलाजी का विकास करना है। संस्थान विभिन्न उद्योगों और ताप बिजली घरों को नियमित रूप से सेवाएं उपलब्ध कराता है।

सेंटर फार इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेशन, भोपाल

विद्युत परिवहन टेक्नोलाजी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1998 में मंजूरी दी गई। केन्द्र की क्षमताओं का विकास किया गया है और यहां बिजली से चलने वाले तमाम वाहनों के डिजाइन संबंधी तमाम पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण कर उनकी कार्यक्षमता, विश्वसनीयता तथा दक्षता में सुधार किया जाता है। केन्द्र में ऐसी सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें सभी परिस्थितियों में वाहनों की कार्यक्षमता का कम्प्यूटरों के जरिये और वास्तविक तौर पर परीक्षण संभव हो सकेगा।

सेरेमिक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर

चानी मिट्टी पर अनुसंधान के लिए सेरेमिक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर की स्थापना का उद्देश्य भारतीय चीनी मिट्टी उद्योग को टेक्नोलाजी के आधुनिकीकरण और परिष्कृत किस्म के उत्पादों के विकास में मदद देना है। उद्योग के लिए आवश्यक कई उत्पादों का विकास किया गया है और उनमें से कुछ का व्यावसायिक उपयोग किया जाने लगा है। 50 से अधिक संगठनों को परीक्षण और मूल्यांकन संवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरूचिरापल्ली

वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान देश में अपनी तरह का पहला है। इसकी स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के वित्त पोषण तथा तकनीकी सहायता से की गयी थी। संस्थान में अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रान और लेजर बीम, फ्लेशबट, घर्षण और प्लाज्मा वैल्डिंग के अलावा परम्परागत आर्क वेल्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यहां फेटीग टैस्टिंग रेजीडयूअल स्ट्रेम मेजरमेंट, रेजीडयूअल लाइफ ऐस्टीमेशन आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डब्ल्यूआरआई ने जर्मनी की जीटीजेड कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके अनुसार इस समय चल रहे परियोजना के दूसरे चरण में वेल्डिंग के संबंध में सहकारी अनुसंधान परियोजना शुरू की जाएंगी।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

इस विभाग के सरकारी क्षेत्र के उद्यम सरकारी निदेशों के अनुपालन द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण को बढ़ावा देने के अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। विभाग के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांगों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्तियों/पदोन्नतियों में आरक्षण से संबंधित सरकारी अनुदेशों का आमतौर पर पालन किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में वे पूर्ण रूप मुख्य धारा में शामिल हैं और उनके साथ पंथ या धार्मिक विश्वास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आवास जैसी सुविधाओं के मामले में सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।

हर वर्ष कौमी एकता/सद्भावना दिवस समारोह मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए एकत्र होते हैं।

सर्तकता

1. विभाग के सतर्कता संगठन की देखरेख एक संयुक्त सचिव करते हैं, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए एक उप सचिव, एक अवर सचिव तथा सहायक कर्मचारी हैं।

2. सतर्कता अनुभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्षण में सतर्कता मामलों की देखरेख करता है। सर्तकता अनुभाग के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं:

   - बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करना;
   - सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों तथा बोर्ड स्तर से नीचे की नियुक्तियों, दोनों और एसीसी के अनुमोदन वाली पीईएसबी की सिफारिशों पर आधारित अन्य सभी नियुक्तियों के बारे में सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना;
   - केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
   - वित्तीय अनियमितता तथा कार्यविधि संबंधी अनौचित्य के मुद्दों पर सलाह देना;
   - बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

3. निवारक सतर्कता पर पूरा बल दिया जाता है और आवश्यकता होने पर उचित मामलों में दण्डात्मक उपाय किए जाते हैं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके मामलों में भारी कमी आई है।

4. सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्राधीन सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों तथा अचल संपत्ति रिटर्न के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और सभी सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों की वार्षिक संपत्ति विररणी को भी मॉनीटर करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का रखरखाव करता है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा सक्रिय प्रयास जारी रहे।

2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., हरिद्वार और दिल्ली का निरीक्षण किया तथा समिति ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर संतोष व्यक्त किया है। विभाग के अधिकारियों ने हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ उद्यमों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए और उनके मुख्य कार्यपालकों को सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया।

3. सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों और परिपत्रों तथा संसद के दोनों पटलों पर रखे गए संसद प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्टें, सामान्य आदेश और कागजात हिन्दी व अंग्रेजी में जारी किए गए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए गए। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिन्दी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए 20.5.2002 से 31.5.2002 तक एक विशेष ''हिन्दी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया था। सितम्बर–अक्तूबर, 2002 में महीना भर हिन्दी दिवस'' आयोजित किया गया, जिसमें इस दौरान हिन्दी नोटिंक/ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन और पैराग्राफ लेखन सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस विभाग के कर्मचारियों ने इन गतिविधियों में बड़ी रूचि के साथ भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरसकार प्रदान किए गए। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग/ ड्रॉफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4. इस वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए:–

(i) राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को आदेश द्वारा उन कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करना होता है, जहाँ टिप्पण, प्रारूपण के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है। तदानुसार, इस विभाग ने नियम 8(4) के प्रयोजनार्थ इस विभाग के बजट एवं लेखा अनुभाग, वित्त–III और समन्वयन अनुभाग को 20.2.2002 को अधिसूचित कर दिया है। यह एकक हिन्दी में अपना सारा कार्य करने के लिए पहले से ही अधिसूचित विभाग के छह अनुभागों के अतिरिक्त है।

(ii) राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तदनुसार, इस विभाग ने एचएमटी, बंगलौर और हिन्दुस्तान केबल्स लि. कलकत्ता को अधिसूचित कर दिया है, क्योंकि उनके 80 प्रतिशत में अधिक कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(iii) ''आज का शब्द'' के माध्यम से हिन्दी सीखने के कार्यक्रम को सक्रियता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

5. विभाग के प्रशासनाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में ''हिन्दी पखवाड़ा''/''हिन्दी दिवस''बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सरकारी उद्यमों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों में हिन्दी में लिखे गए लेख काफी संख्या में शामिल रहते हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

1. उद्योग क्षेत्र भारतीय संविधान और इसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित लिंग की समानता के सिद्धांतों के प्रति जागरुक है।

2. महिला आन्दोलन तथा गैर-सरकारी संगठनों के व्यापक नेटवर्क, जिसकी निचले स्तर तक उपस्थिति है और महिलाओं की चिन्ताओं की गहरी जानकारी है, ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु पहल करने की दिशा में प्रेरणा दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कतिपय अनुपालन योग्य दिशानिर्देश तथा मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

3. मानवाधिकारों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के मामले में पर्याप्त जागरुकता पैदा करने के लिए भारी उद्योग विभाग में लिंग की समानता के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने तथा कामकाजी महिला कर्मचारियों को न्याय के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 को अपने कार्यलय ज्ञापन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशें एवं मानदण्डों के बारे में सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को अनुपालन तथा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक हेतु सूचित कर दिया है।

4. यह विभाग महिला कर्मचारियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण इत्यादि में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने के लिए सक्रियता से प्रोत्साहित करता है। इससे उनके मुख्यधारा कार्यबल से जुड़ने में सहायता मिलती है।

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम की स्थापना का वर्ष	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार सकल परिसंपत्ति
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए वाई एंड कं.), कोलकाता	1979	189.06
2	हुगली प्रिंटिंग, कोलकाता	1979	1.66
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), नई दिल्ली	1956	3239.00
4	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) कोलकाता	1976	130.18
5	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1973	59.62
6	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1976	40.50
7	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), पटना	1978	16.65
8	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1987	7.08
9	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापट्टनम	1966	77.32
10	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	37.60
11	रिचर्डसन एंड क्रूडास (आर एंड सी), मुम्बई	1972	34.22
12	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	20.12
13	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड हासपेट, कर्नाटक	1967	22.34
14	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता	1972	86.44

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम की स्थापना का वर्ष	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार सकल परिसंपत्ति
15	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	529.22
16	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	305.41
17	एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी), बंगलौर	1953	116.05
18	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बंगलौर	1999	211.95
19	एचएमटी वाचेज लि., बंगलौर	1999	189.30
20	एचएमटी चिनार वाचेज लि., बंगलौर	2000	10.37
21	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल) सिकन्दराबाद	1959	37.40
22	एचएमटी (बियरिंगस) बंगलौर	1981	28.33
23	एचएमटी (इंटरनेशनल) बंगलौर	1974	15.37
24	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	62.23
25	आरईआईएल, जयपुर	1981	6.41
26	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल), कोलकाता	1957	8.79
27	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल), लखनऊ	1972	39.40
28	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) दुर्गापुर	1972	5.91
29	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	625.16
30	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	744.24
31	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) तुली, नागालैंड	1971	74.36
32	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), वेल्लोर, कोट्टायम	1983	274.29

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम की स्थापना का वर्ष	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार सकल परिसंपत्ति
33	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	715.05
34	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	4.04
35	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) जयपुर	1964	6.31
36	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1949	114.37
37	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	127.62
38	भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी), आगरा	1976	2.04
39	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	16.34
40	नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी), नई दिल्ली	1954	2.40
	जोड़		**8234.15**

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुलग्नक - II

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार अनु. जाति/अनु. जनजाति सहित भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नियोजन की स्थिति

क्रमांक	सरकारी उद्यम का नाम	कर्मचारियों की संख्या				अनु. जाति के कुल कर्मचारियों की संख्या	अनु. जनजाति के कुल क्कर्मचारियों की संख्या
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी	309	141	15814	16264	1976	4198
2	हुगली प्रिंटिंग	10	8	56	74	1	–
3	भेल	10117	7471	29928	47516	8577	1774
4	बीएससीएल	190	326	1960	2476	–	–
5	जेसप (सहायिका बीबीयूएनएल)	194	80	1221	1495	70	9
6	ब्रेथवेट	127	65	988	1180	130	–
7	बीडब्ल्यूईएल	78	100	1426	1604	123	3
8	बीबीजे	42	0	73	115	12	1
9	बीएचपीवी	532	745	1145	2422	409	133
10	बीपीसीएल	292	103	1127	1522	256	4
11	आर एंड सी	98	–	390	488	139	30
12	टीएसएल	123	137	514	774	75	1
13	टीएसपी	68	36	413	517	158	21
14	बी एंड आर	769	307	484	1560	212	3
15	एचसीएल	420	409	2528	3357	893	246
16	एचईसी	1038	743	3456	5237	372	1091
17	एचएमटी	434	103	2272	2809	636	114
18	एचएमटी (एमटी)	1411	229	3414	5054	860	215
19	एचएमटी (वाचेज)	586	170	2682	3438	595	165
20	एचएमटी (चिनार वाच)	38	92	632	762	54	4
21	प्रागा टूल्स लिमिटेड	122	9	614	725	133	13
22	एचएमटी (बी)	118	41	505	664	70	1

क्रमांक	सरकारी उद्यम का नाम	कर्मचारियों की संख्या				अनु. जाति के कुल कर्मचारियों की संख्या	अनु. जनजाति के कुल क्कर्मचारियों की संख्या
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	एचएमटी (आई)	60	4	15	79	11	2
24	आईएल	289	860	1019	2168	334	93
25	आरईआईएल	43	33	99	175	37	3
26	एनआईएल	15	113	351	479	91	14
27	एसआईएल	242	97	1563	1902	311	2
28	बीओजीएल	13	2	185	200	21	4
29	सीसीआई	303	336	2374	3013	493	227
30	एचपीसी	645	240	2262	3147	313	246
31	एनपीपीसी	13	7	332	352	5	186
32	एचएनएल	230	81	942	1253	86	4
33	एचपीएफ	121	69	1298	1488	244	64
34	एचएसएल	15	39	101	155	22	7
35	एसएसएल	7	35	155	197	63	10
36	नेपा	190	0	1708	1898	153	33
37	टीसीआईएल	67	49	566	682	24	5
38	बीएलसी	–	–	–	–	–	–
39	ईपीआईएल	463	53	101	617	101	15
40	एनआईडीसी	92	7	22	121	17	5
	कुल	**19924**	**13340**	**84725**	**117985**	**18077**	**8947**

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1999-2000 (वास्तविक)	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (संभावित)	2003-2004 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	196.57	167.02	112.45	139.36	190.52
2	हुगली प्रिंटिंग	3.14	3.32	7.11	7.50	7.75
3	भेल	6634.00	6348.00	7287.00	7600.00	8200.00
4	बीएससीएल	217.71	235.02	118.79	204.82	226.69
5	जेसप	48.26	53.48	58.75	64.22	61.48
6	ब्रेथवेट	118.59	147.11	75.20	99.88	109.62
7	बीडब्ल्यूईएल	57.41	113.10	74.54	74.80	116.44
8	बीबीजे	24.18	37.51	36.47	38.00	40.00
9	बीएचपीवी	140.01	264.27	223.17	250.00	270.00
10	बीपीसीएल	42.53	59.51	66.42	85.00	90.00
11	आर एंड सी	73.51	74.90	67.11	65.00	75.00
12	टीएसएल	16.57	13.70	21.60	30.00	35.00
13	टीएसपी	40.93	37.42	15.03	20.00	30.00
14	बी एंड आर	324.45	334.49	347.06	380.00	410.00
15	एचसीएल	803.51	875.08	579.08	607.50	773.52
16	एचईसी	273.42	147.19	162.10	230.52	252.08
17	एचएमटी	718.18	296.57	217.68	263.50	320.10
18	एचएमटी (एमटी)	0.00	200.95	227.76	250.00	300.00
19	एचएमटी (वाचेज)	0.00	144.08	79.05	120.00	200.00
20	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0.00	1.78	2.11	3.73	9.00
21	प्रागा टूल्स लि.	14.06	6.42	3.98	10.03	16.51

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1999-2000 (वास्तविक)	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (संभावित)	2003-2004 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
22	एचएमटी (बी)	47.35	45.00	41.68	35.62	54.00
23	एचएमटी (आई)	42.47	46.81	58.69	71.03	91.39
24	आई एल	124.48	106.74	107.85	152.50	185.00
25	आरईआईएल	20.33	27.45	30.78	31.63	36.05
26	एनआईएल	3.01	5.63	5.48	6.35	7.10
27	एसआईएल	132.05	116.79	129.66	127.61	145.91
28	बीओजीएल	3.07	3.71	3.09	2.65	2.92
29	सीसीआई	134.88	71.99	137.02	166.77	293.48
30	एचपीसी	393.54	468.83	521.73	542.17	561.20
31	एनपीपीसी*	–	–	–	–	–
32	एचएनएल	195.77	254.02	242.24	214.08	241.50
33	एचपीएफ	47.99	31.97	42.40	30.00	37.75
34	एचएसएल	3.82	5.10	5.52	7.71	9.94
35	एसएसएल	5.17	3.83	6.09	7.38	9.10
36	नेपा	97.97	131.75	99.97	72.41	113.75
37	टीसीआईएल	126.91	93.57	64.98	105.60	149.92
38	बीएलसी	1.74	2.09	–	–	–
39	ईपीआई	171.05	260.97	390.53	417.84	512.63
40	एनआईडीसी	6.85	4.28	0.07	0.00	0.00
	कुल	**11305.48**	**11241.45**	**11670.24**	**12535.21**	**14185.35**

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

* कोई उत्पादन नहीं हो रहा।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का (कर-पूर्व) लाभ (+) / हानि(-) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1999-2000 (वास्तविक)	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (संभावित)	2003-2004 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क)	**लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
1	हुगली प्रिंटिंग	0.07	0.05	0.41	0.78	0.82
2	भेल	865.00	294.00	663.00	778.00	894.00
3	बीबीजे	10.00	0.60	0.57	-0.18	-1.39
4	बीएचपीवी	-20.36	0.94	1.71	1.30	2.20
5	एचपीसी	10.60	32.80	63.75	36.81	48.10
6	बी एंड आर	6.58	3.39	3.60	4.00	5.00
7	ईपीआई	-48.14	17.76	9.44	3.00	9.00
8	एचएमटी	-296.91	24.41	10.24	14.70	4.24
9	एचएमटी (बी)	3.50	2.16	0.94	-2.15	2.60
10	एचएमटी (आई)	0.39	0.38	0.54	0.77	1.37
11	आरईआईएल	0.67	0.43	0.60	0.70	1.05
12	एसआईईएल	6.78	5.10	2.26	1.10	1.98
13	एचएनएल	7.21	30.35	6.45	-13.29	-0.19
	(क) उप-जोड़ लाभ कमा रही कंपनियां	**545.39**	**412.37**	**763.51**	**825.54**	**968.78**
(ख)	**हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
14	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी	1.56	-26.78	-39.45	-12.52	1.48
15	ब्रेथवेट	-14.13	1.74	-33.55	-19.21	-15.37
16	टीएसपी	0.11	0.07	-20.03	-6.00	-3.50
17	बीपीसीएल	-19.30	-5.59	-12.46	0.10	1.40
18	बीएससीएल	-35.41	-45.22	-78.35	-55.37	-51.63
19	जेसप	-43.93	-48.77	-47.60	-54.68	-57.52
20	बीडब्ल्यूईएल	-10.78	-4.69	-26.87	-18.81	-11.51
21	आर एंड सी	-1.66	-8.15	-19.21	-9.00	-6.00
22	टीएसएल	-26.77	-45.92	-12.23	-8.10	-5.00

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1999-2000 (वास्तविक)	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (संभावित)	2003-2004 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
23	एचसीएल	-39.32	-71.41	-236.08	-244.49	-236.31
24	एचईसी	-57.06	-189.26	-139.40	-60.15	-37.83
25	एचएमटी (एमटी)	0.00	-96.17	-70.65	-62.65	-38.61
26	एचएमटी (वाच)	0.00	-59.18	-108.29	-59.15	2.18
27	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0.00	-7.95	-10.16	-10.91	-21.39
28	पीटीएल	-29.11	-34.42	-35.06	-15.78	-8.20
29	आईएलके	-28.35	-34.52	-30.49	-25.88	-10.05
30	एनआईएल	-6.57	-4.48	-15.90	-4.02	-4.15
31	बीओजीएल	-37.69	-24.88	-31.87	-35.39	-39.74
32	सीसीआई	-216.91	-230.76	-215.33	-240.89	-240.63
33	एनपीपीसी	-15.00	-15.26	-26.43	-13.36	-16.56
34	एचपीएफ	-278.45	-328.16	-353.72	-376.89	-414.17
35	एचएसएल	-2.91	-2.19	-1.91	-0.88	-0.90
36	एसएसएल	-2.03	-3.27	-3.02	-1.69	-1.75
37	नेपा	9.52	4.86	-35.16	-43.39	-31.39
38	टीसीआईएल	-60.62	-66.43	-67.41	-58.75	-55.18
39	बीएलसी	-3.03	-2.42	*	*	*
40	एनआईडीसी	-5.02	-6.83	-10.87	*	*
(ख)	**उपजोड़ हानि उठा रही कम्पनियां**	**-922.86**	**-1356.05**	**-1671.50**	**-1437.86**	**-1302.33**
कुल जोड़ (क+ख)		**-377.47**	**-943.67**	**-907.99**	**-612.32**	**-333.55**

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीआईएनएल) हैं।

* प्रचालन कार्य बंद कर दिया गया है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक ऊपरी खर्चों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशत					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक ऊपरी खर्च का प्रतिशत				
		1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (अनुमानित)	2002-03 (संभावित)	2003-04 (लक्ष्य)	1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (वास्तविक)	2002-03 (संभावित)	2003-04 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	21.63	34.13	47.58	37.08	26.08	3.97	4.92	6.60	5.16	3.70
2	हुगली प्रिंटिंग	31.52	30.87	21.78	15.43	16.55	2.74	2.74	1.31	1.37	1.39
3	भेल	19.76	26.09	19.83	19.70	19.27	3.44	3.28	3.14	3.13	2.99
4	बीएससीएल	40.57	39.94	42.77	17.70	13.85	3.17	2.89	4.68	1.88	1.37
5	जेसप	87.50	64.80	40.58	42.26	37.53	4.00	3.10	2.44	2.54	2.26
6	ब्रेथवेट	37.84	23.97	52.64	26.17	17.67	2.20	1.30	2.78	2.85	1.82
7	वीडब्ल्यूईएल	58.30	37.90	57.20	41.70	100.00	1.60	0.90	0.80	0.90	0.30
8	बीबीजे	20.20	14.40	12.31	14.82	16.00	1.13	0.91	0.90	1.02	1.00
9	बीएचपीवी	39.44	20.25	21.16	15.72	12.37	4.10	2.54	2.79	2.20	2.15
10	बीपीसीएल	52.02	49.44	32.66	25.49	20.80	5.56	5.38	3.79	2.86	2.53
11	आर एंड सी	17.88	8.31	10.96	8.60	6.79	1.30	1.07	0.92	0.63	0.55
12	टीएसएल	114.81	97.73	41.06	27.83	22.17	13.52	18.25	6.81	2.17	1.82
13	टीएसपी	30.61	25.35	57.41	30.65	19.13	2.06	1.40	3.38	2.35	1.20
14	बी एंड आर	11.32	10.61	10.64	10.16	9.74	0.68	0.84	0.78	0.59	0.49
15	एचसीएल	6.08	5.96	10.33	10.04	7.73	1.15	1.11	1.18	1.11	0.87
16	एचईसी	37.03	67.44	46.21	20.12	15.27	5.65	13.13	7.06	2.87	0.00
17	एचएमटी	44.22	23.04	21.13	17.47	15.63	5.17	2.56	2.58	2.27	2.07
18	एचएमटी (एमटी)	—	59.00	39.00	31.00	28.00	—	8.00	4.00	3.00	3.00
19	एचएमटी (वाचेज)	—	58.73	67.74	47.50	28.50	—	14.08	20.45	11.69	7.19
20	एचएमटी (चिनार)	—	499.00	511.00	325.00	146.00	—	47.00	69.00	46.00	19.00
21	प्रागा टूल्स	40.00	52.00	43.00	40.00	31.00	13.00	15.00	12.00	11.00	9.00
22	एचएमटी (बी)	25.00	27.00	30.00	32.00	24.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
23	एचएमटी (आई)	4.84	5.15	3.23	3.06	3.26	1.03	1.07	0.07	0.44	0.02
24	आईएल	36.26	39.38	36.87	24.82	19.19	2.29	2.20	2.05	1.38	1.14
25	आईआईएल	11.80	13.40	11.23	11.00	10.44	2.93	2.62	2.54	1.75	1.65
26	एमआईएल	128.00	62.00	64.00	43.00	29.00	0.34	0.18	0.16	0.15	0.13
27	एसआईएल	17.72	18.87	18.65	18.99	17.78	4.55	4.44	4.63	4.66	4.13
28	बीओजीएल	137.50	107.39	83.82	76.22	69.18	55.00	31.03	23.24	16.23	14.73
29	सीसीआई	37.03	74.20	32.65	22.08	10.88	2.30	4.86	2.00	1.42	0.89
30	एचपीसी	9.73	9.71	8.56	8.24	8.28	5.01	5.30	6.57	6.13	5.70
31	एनपीपीसी	—	—	—	—						
32	एचएनएल	9.28	8.51	9.74	8.13	7.83	4.77	5.17	5.47	4.85	4.51
33	एचपीएफ	87.59	91.15	70.74	66.92	54.60	2.66	3.77	2.38	1.67	1.27
34	एचएसएल	82.61	69.08	64.67	45.48	36.72	6.00	6.11	4.89	3.53	3.02
35	एमएसएल	73.74	90.43	43.06	34.74	32.34	5.67	7.05	3.65	2.47	2.32
36	नेपा	16.00	12.00	20.00	18.00	11.00	3.00	2.00	3.00	1.00	0.01
37	टीसीआईएल	23.41	34.28	31.70	18.20	8.47	4.53	5.65	4.26	4.54	2.99
38	बीएलसी*	37.00	33.00	14.00	—	—	1.22	1.02	0.37	—	—
39	ईपीआईएल	10.93	6.85	4.41	4.46	3.35	1.23	1.01	0.91	1.34	0.78
40	एनआईडीसी	55.57	77.56	68.07	121.16	—	10.14	16.22	1.99	0.70	—

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीआईएनएल) हैं।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की क्रयादेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सरकारी उद्यम का नाम	दिनांक 1.10.1998 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.1999 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	123.34	117.35	130.78	140.05	131.66
2	हुगली प्रिंटिंग	0.20	0.30	0.20	2.60	2.50
3	भेल	10086.00	10082.00	10526.00	10029.00	12573.00
4	बीएससीएल	181.62	112.50	123.20	0.87	1.11
5	जेसप	87.52	32.89	68.47	63.95	58.67
6	ब्रेथवेट	101.64	155.23	156.20	19.98	106.85
7	बीडब्ल्यूईएल	43.93	77.79	108.56	33.24	32.68
8	बीबीजे	20.55	30.19	57.79	40.09	51.99
9	वीएचपीवी	175.50	158.52	309.20	183.05	130.41
10	बीपीसीएल	20.20	26.24	66.10	73.91	38.83
11	आर एंड सी	105.40	83.21	96.80	79.71	158.15
12	टीएसएल	65.20	50.85	46.70	38.58	37.72
13	टीएसपी	27.20	26.43	55.00	25.95	32.65
14	बी एंड आर	297.60	239.73	325.40	375.77	385.16
15	एचसीएल	4.00	72.16	185.49	243.49	351.63
16	एचईसी	234.80	169.03	150.93	150.32	99.63
17	एचएमटी	—	—	—	—	—
18	एचएमटी (एमटी)	141.98	140.57	133.00	145.08	99.19
19	एचएमटी (वाचेज़)	—	—	—	—	—
20	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	—	—	—	—	—
21	प्रागा टूल्स	21.53	12.34	12.74	8.12	5.30
22	एचएमटी (बी)	14.76	18.02	2.25	2.28	4.37
23	एमएमटी (आई)	33.61	28.19	38.30	42.53	53.15
24	आई एल	55.00	64.00	36.03	34.85	53.82
25	आरईआईएल	3.55	4.91	6.04	19.43	16.94
26	एनआईएल	3.38	4.14	2.16	2.51	2.13
27	एसआईएल	—	—	—	—	—
28	बीओजीएल	0.58	0.41	0.44	0.52	0.53
29	सीसीआई	20.00	22.30	12.29	110.41	4.17
30	एचपीसी	4.17	9.37	24.89	24.10	4.15
31	एनपीपीसी	—	—	—	—	
32	एचएनएल	—	—	—	—	
33	एचपीएफ	—	—	—	1.36	4.00
34	एचएसएल	2.04	1.00	2.21	0.39	3.22
35	एसएसएल	2.93	2.05	1.20	2.10	1.03
36	नेपा	8.12	16.25	27.80	6.59	5.94
37	टीसीआईएल	13.14	15.84	9.00	5.00	4.72
38	बीएलसी	0.72	1.17	1.80	—	—
39	ईपीआईएल	158.68	261.00	430.00	626.45	595.78
40	एनआईडीसी	0.15	4.85	13.06	0.39	0.00
	जोड़	**12059.05**	**12040.83**	**13160.03**	**12532.67**	**15051.08**

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीआईएनएल) हैं।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात–निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम	1998-99			1999-2000			2000-2001			2001-2002			2002-2003 (अनुमानित)		
		वास्तविक	मानित	जोड़	वास्तविक	मानित	जोड़	वास्तविक	मानित	जोड़	वास्तविक	मानित	जोड़	वास्तविक	मानित	जोड़
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं. लि.	16.89	17.31	34.20	10.49	17.79	28.28	8.86	12.00	20.86	8.09	0.00	8.09	10.50	5.60	16.10
2	भेल	69.00	1902.00	1971.00	355.00	1395.00	1750.00	247.00	1426.00	1673.00	987.00	1524.00	2511.00	889.00	1171.00	2060.00
3	बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि.	1.81	12.95	14.76	2.69	0.17	2.86	2.80	0.00	2.80	4.89	0.00	4.89	3.36	19.09	22.45
4	जेसप एंड कं. लि.	1.26	0.00	1.26	0.24	0.00	0.24	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.24	0.00	0.24
5	ब्रेथवेट एंड कं. लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	भारत बैगन इंजी. कं. लि.	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	भारत हैवी प्लेटस एंड वैमल्स लि.	0.00	19.99	19.99	12.78	5.19	17.97	2.00	2.92	4.92	0.00	6.37	6.37	0	2.32	2.32
8	भारत पम्पस एंड कंप्रैशर्स लि.	0.00	0.02	0.02	0.00	0.14	0.14	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	रिचर्डस एंड क्रूडास (1972) लि.	1.44	0.00	1.44	0.41	3.06	3.47	0.34	0.99	1.33	0.24	0.30	0.54	0.25	0.50	0.75
10	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लि.	2.05	2.35	4.40	2.58	7.03	9.61	2.58	7.03	9.61	1.69	1.86	3.55	0.00	1.50	1.50
12	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	8.47	0.00	8.47	12.00	0.00	12.00
13	हिन्दुस्तान केवल्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हैवी इंजीनियरिंग कं. लि.	0.00	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	एचएमटी (एमटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	एचएमटी (वाच)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	प्रागा टूल्स लि.	0.66	0.00	0.66	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	एचएमटी (वियरिंग्स) लि.	0.20	0.00	0.20	0.05	0.00	0.05	0.11	0.00	0.11	0.15	0.00	0.15	0.10	0.00	0.10
19	एचएमटी(आई) लि.	32.74	0.00	32.74	34.37	0.00	34.37	39.18	0.00	39.18	49.68	0.00	49.68	63.50	0.00	63.50
20	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	0.13	0.45	0.58	0.10	1.40	1.50	0.80	0.00	0.80	0.25	1.34	1.59	1.00	1.50	2.50
21	आरईआई लि.	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.25	0.00	0.25	0.08	0.00	0.08	0.20	0.00	0.20
22	एनआईएल	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	स्कूटर्स इंडिया लि.	3.21	0.00	3.21	6.26	0.00	6.26	1.29	0.00	1.29	0.28	0.06	0.34	1.00	0.50	1.50
24	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	3.21	0.21	3.42	26.90	3.21	30.11	3.39	14.58	17.97	0.00	25.17	25.17	0.00	9.55	9.55
25	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. कं.	0.04	0.00	0.04	0.01	0.00	0.01	0.36	0.00	0.36	0.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00
26	हिन्दुस्तान साल्ट लि.	1.08	0.00	1.08	0.73	0.00	0.73	0.81	0.00	0.81	0.92	0.00	0.92	1.10	0.00	1.10
27	सांभर साल्टस लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
28	इंजीनियरिंग प्रो. (इंडिया) लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
	कुल	**135.24**	**1961.65**	**2096.89**	**453.20**	**1432.99**	**1886.19**	**318.70**	**1467.67**	**1786.37**	**1062.38**	**1559.10**	**2621.48**	**983.35**	**1211.56**	**2194.91**

31.3.2002 के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल परिसंपत्ति और संचयी लाभ(+)/हानि(−)

(करोड़ रुपए)

क्र. संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल परिसंपत्ति	संचयी लाभ(+)/हानि(−)
		सरकारी/सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	50.03	3.93	−28.13	−76.35
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03	—	1.17	0.14
3	भेल	191.00	54.00	4221.00	4225.00
4	बीएससीएल	127.51	—	−401.78	−420.78
5	जेसप	93.76	1.32	−311.52	−398.78
6	ब्रेथवेट	105.65	—	−51.90	−150.79
7	बीडब्ल्यूईएल	9.99	—	−31.18	−41.17
8	बीबीजे	2.14	—	0.1	−2.04
9	बीएचपीवी	73.57	—	49.07	−4.01
10	बीपीसीएल	53.53	—	−67.59	−120.26
11	आर एंड सी	54.84	—	−45.65	−77.77
12	टीएसएल	21.02	—	−159.01	−178.77
13	टीएसपी	6.69	1.75	−14.04	−22.07
14	बी एंड आर	13.98	—	40.99	27.01
15	एचसीएल	415.19	1.67	−393.63	−810.49
16	एचईसी	448.12	—	−1067.33	−1494.01
17	एचएमटी	459.67	8.50	55.50	−368.92
18	एचएमटी (मशीन टूल्स)	10.70	—	−354.32	−166.82
19	एचएमटी (वाच)	5.49	—	−242.92	−165.47
20	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	1.41	—	−51.85	−50.63
21	प्रागा टूल्स	17.06	19.11	−218.36	−254.53
22	एचएमटी (बी)	8.49	0.24	13.39	3.35
23	एचएमटी (आई)	0.48	—	20.94	20.58
24	आईएल	75.75	—	−89.54	−166.31
25	आरईआईएल	0.64	0.61	4.77	3.52
26	एनआईएल	8.31	—	−220.02	−228.31
27	एसआईएल	41.00	1.99	50.34	7.36
28	बीओजीएल	7.14	—	−287.48	−294.24
29	सीसीआई	428.28	—	−1240.97	−1637.61
30	एचपीसी	700.38	—	574.18	−126.20
31	एनपीपीसी	113.92	6.28	−77.18	−197.39
32	एचएनएल	82.54	—	189.20	111.54
33	एचपीएफ	179.93	19.19	−1610.88	−1828.63
34	एचएसएल	8.36	—	−4.91	−14.10
35	एसएसएल	0.60	0.40	−7.13	−9.40
36	नेपा	103.00	2.40	−55.47	−154.60
37	टीसीआईएल	93.10	—	−499.61	−592.20
38	बीएलसी	5.72	—	−24.95	−30.67
39	ईपीआईएल	7.82	0.18	116.51	−846.80
40	एनआईडीसी	1.87	—	−32.36	−34.32
	जोड़	**4029.71**	**121.57**	**−2252.55**	**−6565.94**

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 40 उद्यमों के अलावा दो धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीआईएनएल) हैं।

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एवाई एंड कं.	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
ब्रेथवेट	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीएससीएल	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
सी डॉट	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियम इकानामिक कम्युनिटी
इंओटी	इलैक्ट्रीकली आपरेटेड ट्राली
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबशन
एफससीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटीआई	हिन्दुस्तान मशीन (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
आईएलके	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन

जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन आटोमेटिक एक्सचेंज
एमएमसी	एम ओ यू मानीटरिंग सेल
एमओयू	मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारूति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल वाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनआईडीसी	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसई	पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्डस आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
एसएचए	शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसपीए	शेयर परचेज एग्रीमेंट
एसएसएल	सांभर साल्टस लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएससएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड